वर्ष: 1 अंक: 20

16-30 अप्रैल 2021 (निःशुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

पंचायती राज दिवस पर विशेष

हमारी सशक्त-पारदर्शी पंचायती राज व्यवस्था

पेज:6-7

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी

क्षमता की सही पहचान

उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बौद्धिक क्षमता परखने की शुरुआत की कहानी

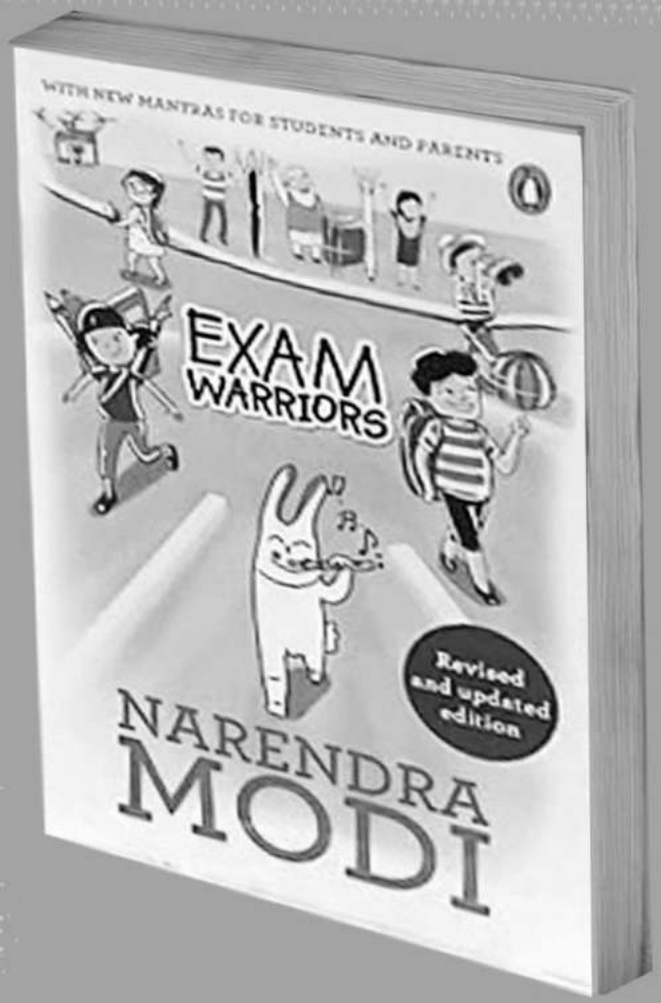

- कोरोना काल के कठिन समय के बाद एक बार फिर परीक्षाओं दौर है। छात्र अक्सर इस समय बेहद तनाव महसूस करते हैं। लेकिन अगर, पढ़ाई सिर्फ परीक्षा के लिए न होकर कुछ नया सीखने के लिए हो तो फिर तनाव खत्म हो जाता है।
- इसी सोच को साकार करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स, जिसका नया संस्करण आ चुका है। नमो एप के साथ अमेजॉन पर भी यह किताब उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इसका किंडल संस्करण भी जारी किया गया है।
- इस बार इस पुस्तक को छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के प्राप्त बहुमूल्य इनपुट से समृद्ध किया गया है। नए भागों को जोड़ा गया है, जो विशेष रूप से माता-पिता और शिक्षकों के लिए रुचिकर होंगे। पुस्तक में नए मंत्र और कई रोचक गतिविधियां हैं। पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने की जरूरत पर बल देती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा...

"एग्जाम वॉरियर्स के इस संस्करण में नए मंत्र और कई रोचक एक्टीविटिज हैं। यह किताब परीक्षा से पहले तनावमुक्त रखने में मदद करती है।"

"

परीक्षा को चिंता नहीं, उत्सव के रूप में देखना चाहिए। हमें असफलताओं को नाकामयाबी के रूप में नहीं देखना चाहिए। अस्थायी असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। वास्तव में इसका यह हो सकता है कि बेहतर आना अभी बाकी है। आपकी प्रतिस्पर्धा स्वयं से होनी चाहिए न कि दूसरों से। सभी चुनौतियों को जीतकर प्रकाशित हों, भविष्य आपके कदमों में होगा। आइए मुस्कान के साथ और बिना चिंता के हम परीक्षा में शामिल हों।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

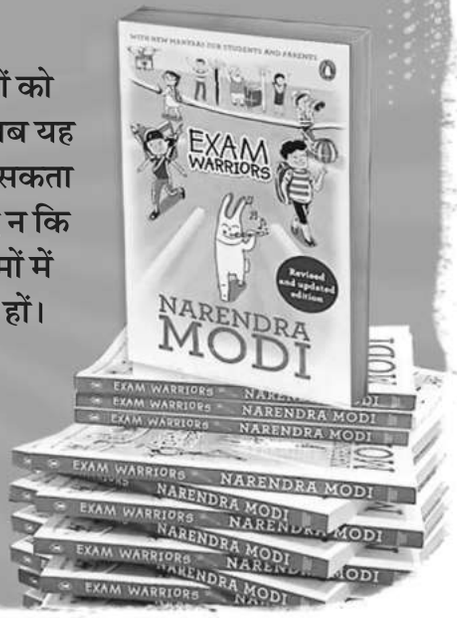

न्यू इंडिया
समाचार
वर्ष: 01, अंक: 20 |16-30 अप्रैल 2021

संपादक
जयदीप भटनागर,
प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

सलाहकार संपादक
संतोष कुमार
विनोद कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश,
प्रधान महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20

संपर्क: ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,सूचना भवन, द्वितीय तल,नई दिल्ली- 110003
ईमेल- **response-nis@pib.gov.in**

डिजाइनर
श्याम शंकर तिवारी

आर. एन. आई. नंबर
DELHIN/2020/78812

अंदर के पन्नों पर...

योग्यता की परीक्षा

आवरण कथा | नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में पहली बार योग्यता की सही पहचान की शुरुआत। पेज 18-24

फ्लैगशिप योजना...

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक: अब आपका बैंक, आपके द्वार

पेज 28-29

नेशनल स्क्रैप पॉलिसी: सबके लिए फायदे का सौदा

आम आदमी के फायदे के साथ पर्यावरण की सुरक्षा का ख्याल

पेज 10-12

समाचार-सार
देश की प्रमुख खबरें। पेज 4-5

हमारी सशक्त-पारदर्शी पंचायती राज व्यवस्था
पंचायती राज दिवस पर केंद्रीय मंत्री का विशेष आलेख। पेज 6-7

मध्यमवर्गीय परिवारों का जीवन बन रहा सुगम
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के जरिए शहरों को मिली रैंकिंग। पेज 8

जिनकी वजह से दुनिया ने भारत के सिनेमा को जाना
महान फिल्मकार सत्यजीत रे की पुण्यतिथि पर विशेष।पेज 9

महिलाओं की प्रेरणा बनीं वेलु, युवाओं की ऊर्जा खुदीराम
भारत के दो महान क्रांतिकारियों का संस्मरण। पेज 16-17

विकास को गति देने के लिए संसाधन जुटाने की नई पहल
कैबिनेट के फैसले। पेज 25

टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में आगे बढ़ रहा भारत
कोरोना से जंग में उठे अहम कदम। 26-27

सुविधाओं के राजमार्ग
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक सुविधाओं का ख्याल। पेज 30-31

चिरंजीवी: भारत-बांग्लादेश मैत्री
बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री का दौरा। पेज 32-35

सदैव देश की सेवा में...
प्रशासनिक सेवा दिवस पर विशेष। पेज 36-37

जिंदगी और पर्यावरण बचाने की अनोखी पहल
कहानी बदलते भारत की। पेज 38

67 वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। पेज 39

प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 22वीं कड़ी
। पेज 40

जल सुशासन से जल संरक्षण का भागीरथी संकल्प

जल संरक्षण की दिशा में जनभागीदारी के साथ 'कैच द रेन' के रूप में महासंकल्प की शुरुआत। पेज 13-15

संपादक की कलम से...

सादर नमस्कार।

आप अपनी 'पत्रिका' को अपार स्नेह दे रहे हैं। कोरोना काल में भी सफलता के कई नए आयाम गढ़ते हुए देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। बीते साल छात्रों ने विपरीत परिस्थिति में भी अपनी पढ़ाई-लिखाई की गति को थमने नहीं दिया। नई तकनीकों ने इसमें महती भूमिका निभाई है। अब परीक्षा का मौसम है, ऐसे में हर क्षेत्र की तरह परीक्षा के मामले में भी केंद्र सरकार ने 2017 में एक क्रांतिकारी बदलाव किया था। अंग्रेजी शासन काल में लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को सिर्फ क्लर्क बनाने भर की शिक्षा पद्धति शुरू की थी, लेकिन आजादी के इतने अरसे बाद भी इसमें बदलाव लाने की बड़ी पहल कभी नहीं हुई।

ऐसे में केंद्र सरकार के प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रूप में एक विशेषज्ञ संस्था मई 2018 में अस्तित्व में आई, जिसने महज तीन साल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ योग्यता और क्षमता की सही पहचान का ढांचा खड़ा कर दिया है। ऑनलाइन सिस्टम की अहमियत का कोरोना काल ने सबको बखूबी अहसास कराया है। यही वजह है कि कोरोना काल में भी परीक्षाएं हुई और छात्रों का साल बर्बाद नहीं हुआ।

इस बार के अंक में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सफलता से लेकर इसकी जरूरत, आवरण कथा बनी है। यह एजेंसी सिर्फ परीक्षाएं ही नहीं ले रही, शिक्षा के तौर-तरीकों, व्यावहारिकता में बदलाव का आधार भी बन रही है, जो देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु है।

आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में गुमनाम नायकों की कहानी, प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा से पड़ोसी देश के साथ रिश्तों के नए युग की शुरुआत, मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव के सूचकांक, स्क्रैप नीति से वाहन मालिकों को तिहरा लाभ, डाक बैंक से ग्रामीणों की बचत को बढ़ावा, राजमार्गों के किनारे जनसुविधाओं-बाजार के विकास की महत्वाकांक्षी योजना और भारतीय सिनेमा को दुनिया में पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रे की कहानी भी इस अंक में शामिल है।

हमेशा की तरह अपना स्नेह और सुझाव देते रहिए।

पता- ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003
ईमेल- response-nis@pib.gov.in

जयदीप भटनागर

(जयदीप भटनागर)

आपकी बात...

न्यू इंडिया समाचार नामक लाजवाब मैगजीन प्रकाशित करने पर हार्दिक मुबारकबाद। इसके ताजा अंक में विभिन्न विषयों जैसे करोड़ों चेहरों पर आई मुस्कान, विदेशी बाजार में छाने को तैयार स्वदेशी खिलौना, क्लस्टर के जरिए परंपरा को जीवित रखने की मुहिम, एक टीका भरोसे का, गरीब कल्याण अभियान, विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी, खेल खेल में ज्ञान और संदेश पर लेख प्रकाशित किये गए हैं। इन सभी लेखों को पढकर हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हुई।
-चौधरी शक्ति सिंह एडवोकेट shaktisinghadv@gmail.com

ये अत्यंत ही गर्व की बात है कि आज स्वदेशी खिलौनों का बाज़ार उत्कृष्टता की शिखर पर पहुंच गया है। हमारा भारत आज निस्संदेह असंख्य परिवार को आत्मनिर्भर बनने का सुअवसर दे रहा है। हां, हम स्वाभिमान से कह सकते हैं कि हमारा देश विश्व में अनूठा है! यहां सबका साथ, सबका विकास संभव है। न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़कर मन संतुष्ट हो गया!
जयंत तपादार
topadarj023@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार एक ज्ञानवर्धक पत्रिका के साथ देश को जागरूक करने की एक प्रक्रिया है। देश को खिलौना उद्योग के क्षेत्र में मजबूत बनाने की सरकार की कार्य योजना काफी प्रशंसनीय है। इस पत्रिका की खासियत है कि यह सभी भाषा में उपलब्ध है।

संध्या निगम
sannigam11@gmail.com

खिलौना उद्योग को समर्पित इस अंक में प्राचीन स्वदेशी खेलों के बारे में काफी रोचक जानकारियां मिली। खासकर, भारत में खिलौना उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम यदि सही दिशा में आगे बढ़ती है तो काफी हद तक विदेशी खिलौनों पर हमारी निर्भरता कम होगी। यह बात भी खास लगी कि आपने कम स्थान पर अधिक से अधिक जानकारियां देने की कोशिश की है। रनिंग मैटर के बजाय ज्यादा प्वाइंटर का प्रयोग बेहतर लगा।
ममता सिंह mamta.07.07@gmail.com

आपकी पत्रिका का डिजिटल संस्करण पाकर मन अभिभूत हो गया। खिलौना उद्योग में भारत की आत्मनिर्भरता पर गहन विश्लेषणात्मक सामग्री के लिए आभार। निश्चित ही यह संस्करण संग्रहणीय है। उम्मीद है कि आगामी अंक भी हमें सुलभ होंगे।
मोहित सोनी
sonimohit895@gmail.com

यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। हमें भारतीय खिलौना उद्योग को सम्पूर्ण विश्व में स्थान दिलाना है। इससे यहां के कारीगरों का हुनर निखर जाएगा।
शैलेन्द्र कुमार
nhpcindia1@gmail.com

मैं न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का नियमित पाठक हूं। इस पत्रिका के माध्यम से हमें केंद्र सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है। यह पत्रिका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अत्यंत उपयोगी है। मेरा एक सुझाव है की पत्रिका का पाक्षिक के स्थान पर साप्ताहिक प्रकाशन किया जाए।
सर्वेश कुमार sarvesh.kr@rb.nic.in

न्यू इंडिया समाचार पढ़ कर बहुत अच्छा लगा। देश की सभी मुख्य खबरों के साथ साथ और भी बहुत जानकारी मिली। यह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की करंट अफेयर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है।
पवन राज कुशवाहा pavanraj282000@gmail.com

पत्रिका का नवीनतम अंक पढ़ा, अच्छा लगा। इस पत्रिका के सभी अंक पढ़े हैं, हमेशा नए अंक की उत्सुकता रहती है। खिलौनों के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। ये पत्रिका मेरे परिवार को भी अच्छी लगती है।
-मनीष कुमार manishk.d089501@gov.in

अब डिजिटल कैलेंडर

भारत सरकार ने पहली बार डिजिटल कैलेंडर और डायरी एप लॉन्च किया है। जीओआई एप पर सभी सरकारी योजनाओं, कार्यक्रम, प्रकाशन के साथ आधिकारिक अवकाश और तिथियों की जानकारी भी मिल जाएगी।

इसे गूगल प्ले स्टोर और आईओएस पर डाउनलोड कर सकते हैं।

गूगल प्ले स्टोर लिंक
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.calendar

आईओएस लिंक
https://apps.apple.com/in/app/goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

पुराने बल्ब देकर 10 रु. में नए एलईडी बल्ब ले सकेंगे ग्रामीण

देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का सपना पूरा करने वाली केंद्र सरकार ने सस्ती और अच्छी रोशनी की दिशा में एक और नया कदम उठाया है। ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब लोग अपने पुराने फिलामेंट वाले बल्ब देकर सिर्फ 10 रुपये में नए एलईडी बल्ब ले सकेंगे। एक परिवार को 7 और 12 वॉट के अधिकतम 5 एलईडी मिलेंगे। केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने बिहार के आरा जिले से इसकी शुरुआत की है। पहले चरण में आरा के साथ वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर और पश्चिमी गुजरात में 1.5 करोड़ एलईडी वितरित किए जाएंगे। यही नहीं, ग्राम उजाला कार्यक्रम पहली ऐसी योजना है जिसमें वित्तीय प्रबंधन कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किया गया है। अब इन एलईडी बल्बों के माध्यम से जहां हर वर्ष 202.5 करोड़ यूनिट(किलोवाट/घंटा) बिजली की बचत होगी, वहीं कार्बन उत्सर्जन में भी 16.5 लाख टन की कमी आएगी। देश के 3 करोड़ 70 लाख घरों में पहले से ही एलईडी बल्ब का उपयोग किया जा रहा है। इससे प्रतिवर्ष 3.80 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।

1 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला एमएसपी पर धान खरीद का लाभ

अन्नदाता को उसकी फसल का सही दाम मिले, केंद्र सरकार अपने इस लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। खरीफ के सीजन में धान की खरीदी के ताजा आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। 21 मार्च तक 21 राज्यों के 100.92 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 685.39 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी अवधि में पिछली साल 603.79 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी। यानी इस साल अब तक 13.51% अधिक धान एमएसपी पर खरीदी गई है। अकेले पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई, यह पूरी खरीद का 29.59% है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के एवज में 1,29,402.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत सरकार ने एमएसपी पर 3,60,238.73 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है। वहीं, 18,97,005 किसानों से 26,719.51 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 91,86,803 गांठों की खरीद की जा चुकी है।

'मेरा राशन' एप से देश के किसी भी कोने में लीजिए अपने हक का राशन

प्रवासी श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए अब केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने नई पहल की है। श्रमिकों को काम करने के लिए अक्सर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, ऐसे में सरकारी सस्ता राशन लेने में उन्हें सुविधा हो इसके लिए MERA RATION मोबाइल एप की शुरुआत की गई है। इस एप की मदद से किसी भी राज्य में किसी भी दुकान से राशन लिया जा सकता है। आधार नंबर के वेरिफिकेशन के साथ यह एप अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है और जल्द ही 14 अन्य भारतीय भाषाओं में भी यह उपलब्ध होगा। इस एप से नजदीकी दुकान की जानकारी भी हासिल की जा सकती है। यह एप केंद्र सरकार की एक देश-एक राशन कार्ड योजना का हिस्सा है। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में चार राज्यों में की गई थी। वर्तमान में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का लाभ अभी तक 69 करोड़ लोग ले चुके हैं। हर माह करीब 1.5 करोड़ लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है।

अटल टिंकरिंग लैब

के छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग के गुर सिखाएगा अमेजॉन वेब सर्विस

छात्रों और युवाओं के सपनों को अनोखे आविष्कार में बदलने की कहानी अब आप कई बार देखते, सुनते या पढ़ते होंगे। चार साल पहले केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए अटल इनोवेशन ने इन छात्रों और युवाओं के वैज्ञानिक सपनों को नए पंख दिए हैं। बच्चों को स्कूल से ही इनोवेटर बनाने के उद्देश्य से अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से आज भारत के 7000 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों के इनोवेशन को नई दिशा दी जा रही है। सफलता की इसी कड़ी में अब एक और नई शुरुआत होने जा रही है। अटल टिंकरिंग लैब के यह छात्र अब अमेजॉन वेब सर्विस के माध्यम से क्लाउड कंम्प्यूटिंग के गुर सीखेंगे। नीति आयोग ने इसके लिए करार किया है। अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक आर रमनन के अनुसार इस करार से अमेजॉन वेब सर्विस देश के प्रतिभावान छात्रों को डिजिटल और वेब आधारित तकनीक सिखाएगा, ताकि उनकी सृजनात्मक और इनोवेशन की क्षमता में बढ़ोतरी हो सके।

अटल पेंशन योजना से सालभर में जुड़े 65 लाख लोग

हर किसी को यह चिंता होती है कि उसे बुढ़ापे में आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी चिंता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जून 2015 को शुरु की गई अटल पेंशन योजना को अच्छा परिणाम मिला है। पेंशन क्षेत्र के नियामक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 तक 2 करोड़ 72 लाख 69 हजार लोगों ने अटल पेंशन योजना में खाता खुलवा लिया था। पिछले साल फरवरी महीने के अंतिम दिन तक इस योजना के खाताधारकों की संख्या 2 करोड़ 7 लाख 41 हजार थी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की 60 वर्ष की आयु होने के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह दी जाएगी। यह लाभार्थियों के द्वारा किए गए निवेश तथा उम्र के हिसाब से निश्चित की जाती है। अटल पेंशन योजना में ना केवल आप कम राशि जमा करवाकर हर माह ज्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु होने पर पेंशनर के परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

बेंगलुरु में बना देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल

हवाई अड्डों की तरह अब रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय रेल ने बेंगलुरु में देश का पहला एयर कंडीशन्ड रेलवे टर्मिनल बना कर विकास की एक और झलक पेश की है। विश्वस्तरीय सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध रेलवे ने इस टर्मिनल का नामकरण देश के अग्रणी सिविल इंजीनियर्स में से एक भारत रत्न, सर एम.विश्वेश्वरय्या के नाम पर किया है। इस रेलवे टर्मिनल पर जल्द ही परिचालन शुरू होगा। करीब 314 करोड़ रुपये की लागत से बना यह स्टेशन 4200 वर्गमीटर में फैला हुआ है और इस पर 50 हजार लोगों की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल विकास की नित-नई ऊंचाईयों को छू रहा है और देश में यह यात्रा का एक लोकप्रिय माध्यम है। भारतीय रेल लगातार ऐसे प्रयासों को बल देती रही है जिससे रेल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके।

आत्मनिर्भर भारत का मार्ग निर्माण करती

हमारी सशक्त-पारदर्शी पंचायती राज व्यवस्था

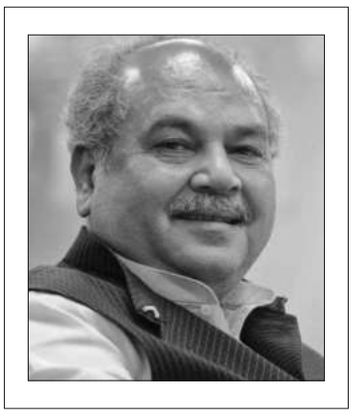

नरेन्द्र सिंह तोमर
पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार

> सशक्त, संसाधनों से युक्त और पारदर्शी पंचायती राज व्यवस्था आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग है।

भारत में एक बार फिर रामराज्य की स्थापना का जो स्वप्न राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था उसकी नींव में देश के सवा छह लाख से ज्यादा गांवों में सशक्त पंचायती राज की व्यवस्था से ग्रामीण विकास का एक सुनियोजित मॉडल भी था। गांधी जी सदैव कहते थे कि सच्चा लोकतंत्र राजधानी में बैठकर राज्य चलाने से नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है।

प्राचीन काल से हमारे देश में गांवों के विकास और वहां के सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखने में पंचायतों की अहम भूमिका रही है। भले इन पंचायतों का कोई संवैधानिक ढांचा न रहा हो, लेकिन पंच और पंचायतें गांवों में विकास के साथ ही आपसी विवाद सुलझाने का एक मजबूत स्तंभ रहे हैं। भारत पर सैंकड़ों वर्ष तक विदेशी आक्रमण हुए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आक्रांता हमारी सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांवों में पंचायतों के माध्यम से गहरी जड़ें जमाए सामाजिक समरसता और एकता के ताने-बाने को नहीं तोड़ पाए। स्वयं अंग्रेज वाइसराय लॉर्ड रिपन प्राचीन भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रशंसक रहे हैं और उन्होंने 1882 में भारत में ग्रामीण स्तर पर जिस स्थानीय स्वशासन की शुरूआत अंग्रेजी राज में की वह हमारी पुरातन पंचायती राज व्यवस्था पर ही आधारित था।

संविधान के 73 वें संशोधन के माध्यम से देश में पंचायती राज व्यवस्था को एक आधारभूत और अधिकार संपन्न ढांचा प्रदान किया गया है। 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम देश में प्रभावी हुआ और इसीलिए हम इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। देश की 2,55,487 ग्राम पंचायतों और लगभग साढ़े सात हजार मध्यवर्ती एवं जिला पंचायतों का संवैधानिक शक्ति प्राप्त ढांचा दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत आधार स्तंभ बनता है। हर पांच साल में ग्रामीण अपने वोट से अपने गांव की सरकार को चुनते हैं और महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि देश के 31.65 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में से लगभग 46 फीसदी अर्थात 14.53 लाख हमारी बहनें हैं, जो पूरी क्षमता एवं कुशलता के साथ गांवों की सरकार को संचालित कर रही हैं।

24 अप्रैल 2020 को पिछला पंचायती राज दिवस कोविड-19 की प्रतिकूलता एवं लॉकडाउन के बीच मनाया गया था। इस अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के पंचायत प्रतिनिधियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए देश के गांवों को दो बड़ी सौगात दी थी। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जिस महात्वाकांक्षी योजना- 'स्वामित्व' का शुभारंभ किया है वह आजादी के बाद अब तक गांवों के आधारभूत ढांचे को मजबूत और सुस्थापित करने में सबसे बड़ा कदम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती के 151 वें वर्ष में गांवों में रह रहे 83 करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकार प्रदान करना बापू को सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि है। ग्रामीणों के पास उनके मकान

का कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था, जो ये दावा करता हो कि वे ही उसके मालिक हैं। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार हो रहे गांवों के डिजिटल नक्शे न केवल ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकार प्रदान करेंगे, बल्कि देश के हर गांव के सुनियोजित विकास का भी आधार बनेंगे। पिछले वर्ष 6 राज्यों में पायलट चरण के रूप में प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना को इस साल केंद्रीय बजट मे संपूर्ण देश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। पिछले पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने एकीकृत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और इसके मोबाइल एप का भी शुभारंभ करके पंचायतों में एक पारदर्शी और त्वरित व्यवस्था की भी शुरूआत की थी।

पिछले पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए जो मंत्र पंचायत जन प्रतिनिधियों के साथ अपनेक संवाद में दिया था, उसी के आधार पर पंचायतों ने कोविड-19 संक्रमण रोकने और आपदा की इस घड़ी में बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य प्रभावितों को जो सहयोग और संबल प्रदान किया है, वह अत्यंत प्रंशसनीय है। संकट के इस काल में मनरेगा और गरीब कल्याण रोजगार योजना ने गांवों में हर गरीब और जरूरतमंद को रोजगार प्रदान कर एक नया इतिहास लिखा है। पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत रिकार्ड 387.66 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ और सवा 11 करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मिला। इसी तरह गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 50.78 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया।

वर्तमान के साथ यहां भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर शहरों की तरह हमने गांवों में सुनियोजित विकास पर ध्यान दिया

हम लगातार सशक्त, पारदर्शी, प्रभावी और जन कल्याण के लिए समर्पित पंचायती राज व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त कर गांवों के विकास के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। चौदहवें वित्त आयोग (वर्ष 2015-2020) के तहत 2 लाख 292 करोड़ रुपये की राशि ग्राम पंचायतों को देने की अनुशंसा की गई, जो तेरहवें वित्त आयोग से तीन गुना ज्यादा थी। विगत वर्ष 2020-21 में पंद्रहवे वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसा के तहत 60750 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई जो कि अब तक का सबसे ज्यादा सालाना आवंटन रहा है, और सरकार ने इसे पूरी तरह से स्वीकार किया है। पंद्रहवें वित्त आयोग (वर्ष 2021-2026) की अनुशंसा में स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये की धन राशि प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए 43,928 करोड़ रुपये अलग से देने की अनुशंसा भी आयोग ने की है। भारत सरकार ने इन अनुशंसाओं को पूर्णतः स्वीकार किया है।

गांवों के सुनियोजित विकास और वित्त आयोग की धनराशि के पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग के लिए देश की 96 फीसदी ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का निर्माण करके उसे लागू करना और इस वर्ष से जिला एवं मध्यवर्ती पंचायतों के द्वारा भी विकास योजनाओं का निर्माण स्वतः सिद्ध करता है कि गांव भी अब शहरों की तरह एक सुनियोजित विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां आज के साथ भविष्य की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं राजधानी में तय नहीं हो रही है अपितु जन योजना अभियान के माध्यम से गाँवों में ही तैयार की जा रही है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2018 में पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) का शुभारंभ किया था। निर्वाचित प्रतिनिधियों अैर पंचायतों के अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए सरकार का यह कदम मील का पत्थर साबित हुआ है। वर्ष 2018 से केंद्रीय वित्त आयोग की निधि के उपयोग के लिए प्रिया सॉफ्ट (Panchayati Raj Institutions Accounting Software)का प्रभावी उपयोग, वित्त आयोग की राशि से निर्मित प्रत्येक परिसंपत्ति जियो टैगिंग और फोटो अपलोड करने जैसी प्रक्रियाओं से पंचायती राज व्यवस्था को पूर्णतः पारदर्शी और त्वरित बना दिया है। ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के माध्यम से जहां पंचायतों के कामकाज में गति आई है, वहीं हर कार्य की रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग भी सरल हुई है। 23 राज्यों में 14 वें वित्त आयोग के खातों के ऑनलाइन ऑडिट का कार्य प्रारंभ हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर सुदूर गांव की पंचायत के बीच की दूरी सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में कम ही नहीं हुई, लगभग समाप्त हो गई है। दिल्ली से यदि अब सौ रूपए जारी होते हैं तो उसकी एक-एक पाई गांव के विकास और कल्याण में उपयोग होती है। पिछले सात वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रभावी सुधारों से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण हुआ है। प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि आत्मनिर्भर गांव ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। सशक्त, संसाधनों से युक्त और पारदर्शी पंचायती राज व्यवस्था आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग है। ●

मध्यमवर्गीय परिवारों का जीवन बन रहा सुगम

> *मध्यमवर्गीय चमत्कार करने की ताकत रखता है। ईज ऑफ लिविंग का सबसे बड़ा लाभ किसी को होना है तो मेरे मध्यवर्गीय परिवारों को होना है। सस्ते इंटरनेट की बात हो, चाहे सस्ते स्मार्टफोन की बात हो या उड़ान के तहत हवाई जहाज के टिकटें बहुत सस्ती हो जाने की बात हो या हमारे हाई-वेज हों या इंफोर्मेशन-वेज हो, ये सारी चीजें मध्यम वर्ग की ताकत बढ़ाने वाली है।*
>
> ——— नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स- 2020 ने बताया कौन से शहर जीवन जीने की सुगमता के मामले में अव्वल है और कहां सरकार की पहल से शहर-नगरपालिकाओं का विकास उसे स्मार्ट सिटी बना खास तौर से मध्यवर्ग के जीवन स्तर में आमूल-चूल बदलाव ला रहा है। स्मार्ट सिटी का मतलब है- शहरों का पुनरुद्धार, सुशासन, जवाबदेही और जीवन जीने की सुगमता

ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की सुगमता जन-जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए योजना बनाना भर ही नहीं, बल्कि उससे आम लोग कैसा महसूस करते हैं, इसी की परख का तरीका है- ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। जिसके जरिए एक तरफ जहां जीवन की गुणवत्ता और शहरों के विकास की असली तस्वीर दिखती है, वहीं सरकार की ओर से दी जा रही सेवाओं के बारे में लोगों का नजरिया भी मालूम पड़ता है। केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च महीने में ऑनलाइन आयोजन में 2020 के लिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स (जीवन जीने की सुगमता सूचकांक) के साथ-साथ नगरपालिका कार्य निष्पादन सूची की अंतिम रैंकिंग जारी की। सूचकांक 2020 में उन शहरों के लिए घोषणाएं की गई हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम है। साल 2020 में आयोजित प्रतियोगिता में 111 शहरों के 32 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ ईज ऑफ लिविंग पर भी प्रधानमंत्री लगातार जोर देते आ रहे हैं। इस सूचकांक का मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन, सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण, बिजली खपत जैसी 13 श्रेणियों में 49 संकेतकों के साथ जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना है। ●

टॉप 10 शहर
(10 लाख से अधिक आबादी)

01. बेंगलुरु
02. पुणे
03. अहमदाबाद
04. चेन्नई
05. सूरत
06. नवी मुंबई,
07. कोयंबटूर
08. वड़ोदरा
09. इंदौर
10. ग्रेटर मुंबई

टॉप 10 शहर
(10 लाख से कम आबादी)

01. शिमला
02. भुवनेश्वर
03. सिलवासा
04. काकीनाडा
05. सलेम
06. वेल्लोर
07. गांधीनगर
08. गुरुग्राम
09. दावणगेरे
10. तिरुचिरापल्ली

शीर्ष नगर पालिकाएं

10 लाख से अधिक आबादी वाली नगरपालिका में इंदौर नंबर वन पर है। उसके बाद सूरत और भोपाल को जगह मिली है। जबकि 10 लाख से कम वाली श्रेणी में नई दिल्ली टॉप पर है। उसके बाद तिरूपति व गांधीनगर का स्थान है।

सत्यजीत रे

जिनकी वजह से दुनिया ने भारत के सिनेमा को जाना

दुनिया के महानतम फिल्मकारों में से एक अकिरो कुरोसोवा ने कहा था- सत्यजीत रे की फिल्मों के बारे में न जानने का मतलब सूरज और चांद विहीन दुनिया में रहना है। महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने 23 अप्रैल के दिन ही हमसे विदा ली थी। पीछे छूट गई 'पथेर पांचाली' जैसी वो फिल्में जिनमें पहली बार दुनिया ने भारत के सिनेमा की झलक देखी...

जन्म: 2 मई 1921 मृत्यु: 23 अप्रैल 1992

बहु दिन धोरे बहु क्रोशे दूरे,
बहु व्यय कोरे बहु देशे घूरे
देखिते गियेछी पर्वत माला
देखिते गियेछी सिंधु
देखा होय नाई चक्षु मेलिया
घर होते सुधु दुई पा फेलिया
एक टि धानेर शीशेर ऊपरे
एक टि शिशिर बिंदु

बांग्ला में लिखी यह कविता गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर ने उस बालक की नोटबुक में लिखी थीं, जो शांति निकेतन में अपनी मां के साथ उनसे मिलने आया था। मां ने मतलब समझाने को कहा तो गुरुदेव बोले- जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। इस कविता के रूप में गुरुदेव से सूत्र लेने वाले इस बालक का नाम माणिक था। जब वह बड़ा हुआ तो दुनिया ने उसे दुनिया के महानतम फिल्मकारों में से एक सत्यजीत रे के नाम से जाना।

2 मई 1921 को कोलकाता में पैदा हुए सत्यजीत रे केवल 3 वर्ष के थे, जब उनके पिताजी नहीं रहे। मां ने उन्हें बड़ी मुश्किल से पाला। उन्होंने सबसे पहले प्रेसीडेंसी कॉलेज और फिर शांति निकेतन में पढ़ाई की। इसके बाद बतौर ग्राफिक डिजाइनर काम करने लगे। जिम कॉर्बेट की 'मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं' और पं. जवाहरलाल नेहरू की 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' का कवर पेज सत्यजीत रे ने ही डिजाइन किया था। 1950 में उनकी कंपनी ने उन्हें लंदन भेजा। लंदन में बिताए उन दिनों ने रे की दुनिया बदल दी। 6 महीनों में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में देखीं। कोलकाता लौटे तो अतिरंजना और नाटकीयता से दूर सार्थक सिनेमा के माध्यम से भारत के गांव के एक परिवार के संघर्ष को 'पथेर पांचाली' के रूप में परदे पर उतारने का निर्णय लिया। 1928 में छपे विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय के इस मशहूर उपन्यास के बाल संस्करण का कवर रे ने ही तैयार किया था। शौकिया कलाकारों और नए-नवेले डायरेक्टर पर कोई पैसा लगाने को भी तैयार नहीं था। बमुश्किल 1955 में यह पर्दे पर आई तो विश्व सिनेमा के मंच पर सबसे ज्यादा सराही गई। 11 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। यह शुरुआत भर थी। इसके बाद तीन दशक से भी लंबे समय तक सत्यजीत रे ने करीब तीन दर्जन फिल्मों का निर्देशन किया। इनमें पारस पत्थर, कंचनजंघा, महापुरुष, अपूर संसार, महानगर, चारूलता, अपराजितो, गूपी गायन-बाघा बायन शामिल हैं। हिंदी में 'शतरंज के खिलाड़ी' का भी निर्देशन किया।

1978 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल की संचालक समिति ने उन्हें विश्व के तीन सर्वकालिक निर्देशकों में से एक के रूप में सम्मानित किया। भारत सरकार की ओर से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं के लिए उन्हें 32 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 1985 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में उन्हें भारत रत्न मिला और ऑस्कर (ऑनरेरी अवॉर्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट) भी। लेकिन रे बीमार थे, इसलिए ऑस्कर लेने नहीं जा सकते थे। उनके घर आकर ऑस्कर अवॉर्ड के पदाधिकारियों ने उनका सम्मान किया। इस आयोजन की फिल्म बनाई गई और उसे ऑस्कर सेरेमनी में प्रदर्शित कर पूरी दुनिया को दिखाया गया। एक महीने के भीतर ही 23 अप्रैल 1992 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। ●

नेशनल स्क्रैपिंग पॉलिसी

सबके लिए फायदे का सौदा

पहले आपको 20 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहन और 15 से ज्यादा पुराने कॉमर्शियल वाहनों को कबाड़ में 4-6 हजार रुपये में बेचना पड़ता था। इस तरह की कबाड़ हुई कई गाड़ियों को आपने अपने आस-पास भी देखा होगा। लेकिन अब ये पुरानी गाड़ियां उनके मालिक के साथ, सरकार और पर्यावरण दोनों के लिए मुनाफे का काम करेंगी तो वहीं देश के वाहन उद्योग को भी स्क्रैपिंग पॉलिसी के साथ मिलेगी नई रफ्तार

भारत में 20 साल से पुराने 51 लाख और 15 साल से पुराने 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं। लगभग 17 लाख मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन हैं, जो 15 साल से अधिक पुराने हैं और उनके पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में पर्यावरण को 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्क्रैपिंग नीति लेकर आई है। यह मानक जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे विभिन्न देशों के मानकों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद बनाए गए हैं।

स्क्रैप पॉलिसी टाइमलाइन

- **01 अक्टूबर 2021** – फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर के लिए नियम
- **02 अप्रैल 2022** – 15 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी और पीएसयू वाहनों की स्क्रैपिंग
- **01 अप्रैल 2023** – भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस टेस्ट:
- **01 जून 2024** – अनिवार्य फिटनेस टेस्ट (अन्य श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से)

लाखों लोगों को नए रोजगार का मौका

स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में वह सब जो आप जानना चाहते हैं

क्या है स्क्रैपिंग पॉलिसी

यह नीति 15 साल पुरानी कॉमर्शियल और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों पर लागू होगी। नीति में 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। लेकिन ऐसी गाड़ियों को चलाने के लिए हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू (पंजीकरण नवीनीकरण) कराने की फीस को बढ़ाकर दो से तीन गुना कर दिया गया है।

- कॉमर्शियल वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र न मिल पाने की स्थिति में 15 वर्ष के बाद उनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा।
- निजी वाहनों के लिए 20 साल के बाद रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण न होने की स्थिति में अथवा अनफिट पाए जाने पर डी-रजिस्टर कर दिया जाएगा। 15 साल की अवधि पूरी कर लेने पर वाहनों को रजिस्ट्रेशन दोबारा करने पर बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगमों, पंचायतों, राज्य परिवहन निगमों और केंद्र एवं राज्य सरकारों के स्वायत्तशासी निकायों के सभी वाहनों को उनके पंजीकरण की तिथि के 15 वर्ष पूरे हो जाने के बाद डीरजिस्टर कर दिया जाएगा।

स्क्रैपिंग की प्रक्रिया क्या होगी

सबसे पहले जानें आपको क्या फायदा होगा

1. स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा पुराने वाहन के लिए दी गई स्क्रैप कीमत, एक नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत का लगभग 4-6% होगी।
2. स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर वाहन निर्माता आपको 5 फीसदी तक डिस्काउंट देंगे। यानी मान लीजिए कि आप ऐसी गाड़ी खरीद रहे हैं, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये है तो आपको इस पर करीब 50 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी। यह छूट वाहन निर्माताओं द्वारा आपको समय-समय पर दिए गए डिस्काउंट के अतिरिक्त होगी।
3. स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को पूरी तरह से माफ किया जा सकता है।
4. राज्यों को निजी वाहनों के लिए 25 फीसदी तक और कॉमर्शियल वाहनों के लिए 15 फीसदी तक रोड टैक्स में छूट देने की सलाह दी गई है।

रिसाइकल से घटेगी लागत...

देश में स्क्रैपिंग सेंटर बनेंगे। स्क्रैपिंग सेंटर पर पुराने वाहनों को रिसाइकल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार जिन देशों में स्क्रैपिंग की सुविधा नहीं है, वहां के वाहनों को भी इन सेंटरों में स्क्रैप किया जा सकता है। इससे एल्युमिनियम, तांबा और रबर की रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिलेगा। वाहन कंपनियों को रिसाइकलिंग से कच्चा माल मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक वाहनों की लागत 40% तक कम होने की उम्मीद है।

दरअसल, केंद्र सरकार का ध्यान ऐसी नीतियों की तरफ है जो आम आदमी को फायदा दें, साथ ही पर्यावरण और उससे जुड़े दूसरे सेक्टर पर भी उसका सकारात्मक असर हो। इसी दिशा में अब नया कदम पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी के रूप में सामने आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी। यह समयबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के काम करने की प्रतिबद्धता ही है कि मात्र 46 दिनों के भीतर 18 मार्च को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री

इस पूरे फायदे को आप इस तरह से समझ सकते हैं

मान लीजिए कि आपने एक गाड़ी स्क्रैपिंग के लिए दी है। बाजार में इस वाहन की कीमत करीब 10 लाख रुपये है। तो स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा इस पुरानी गाड़ी पर आपको अनुमानित 60 हजार रुपये मिल जाएंगे। अब आप 10 लाख रुपये की ही एक्स-शो रूम कीमत वाली नई पेट्रोल गाड़ी निजी उपयोग के लिए खरीदते हैं तो स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार आपको इतना फायदा होगा-

एक्स-शोरूम कीमत
₹ 10,00000

₹600
रजिस्ट्रेशन पर छूट

₹50,000
स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट पर निर्माता द्वारा छूट

रोड टैक्स छूट... पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में 7% रोड टैक्स देना होता है। यानी करीब 70000। तो 25% के हिसाब से छूट- 17500

यानी आपको कुल फायदा
60,000+50,000+600+17,500 = 1,28,100*

*** (अधिकतम छूट के साथ आंकड़ा अनुमानित है। नीति का अंतिम ड्राफ्ट तैयार होने पर इसमें बदलाव संभव है।)**

भारत बनेगा ऑटोमोबाइल हब

50% **वाहन दूसरे देशों में निर्यात करती हैं अभी भारत में वाहन बनाने वाली कंपनियां**

स्क्रैप पॉलिसी में रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलने से लागत और कम होगी और इसके चलते दुनिया में उत्पाद और प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

हर जिले में वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण स्तर मापने के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। इससे आने वाले 5 सालों में देश ऑटोमोबाइल का हब बन सकता है।

10,000
करोड़ का निवेश आएगा इस सिस्टम से

रोजगार के अवसर भी...

35,000

नए रोजगार सीधे तौर पर पैदा होंगे। अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों नए रोजगार सृजित होंगे।

ई-वाहनों को भी बढ़ावा

स्क्रैप नीति के साथ सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को भी और बढ़ावा देगी। ऐसे वाहनों में उपयोग होने वाली 81 फीसदी लीथियम बैटरी देश में बन रही हैं। अगले साल तक 100% बैटरी मेड इन इंडिया होंगी।

प्रदूषण पर लगाम लगेगी, ईंधन भी बचेगा...

- अभी करीब 1 करोड़ वाहन ऐसे दौड़ रहे हैं, जो इस नीति के दायरे में आएंगे। 2025 तक इनकी संख्या करीब 2.8 करोड़ होगी। ये फिट वाहनों की तुलना में 10-12 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।
- ऐसे पुराने वाहनों के सड़कों से हटने पर कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में 17 फीसदी तक की कमी आएगी। वहीं वाहनों से निकलने वाले जहरीले कण 24 फीसदी तक कम हो जाएंगे।
- बीएस-2 और बीएस-3 के वाहन चलन से बाहर हो जाएंगे। इससे करीब 80 लाख टन तक ईंधन की बचत हो सकेगी।

नितिन गडकरी ने इसका ड्राफ्ट भी जारी कर दिया। ड्राफ्ट पर आए सुझावों पर विचार के बाद इसे 1 अक्टूबर से लागू भी कर दिया जाएगा।

आने वाले 5 सालों में इसके जरिए जहां बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे, वहीं हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को नया सहारा भी मिलेगा। उस पर पर्यावरण सुरक्षा के साथ आपकी जेब के लिए भी यह फायदे का सौदा है। सुझावों और राज्य सरकारों की राय के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। ●

जल सुशासन

जल संरक्षण का भागीरथी संकल्प

केंद्र सरकार ने 'वाटर गवर्नेंस' को अपनी नीतियों और निर्णयों में प्राथमिकता पर रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' अभियान, नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना जैसी पहल से जल को जन-जन से जोड़ा है। अब जल संरक्षण की दिशा में जन भागीदारी के साथ 'कैच द रेनः जहां भी, जब भी संभव हो वर्षा का जल संग्रह करें' जैसे अनोखे अभियान और नदी जोड़ो परियोजना की हुई ऐतिहासिक शुरुआत

> *जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी, एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है पारस के स्पर्श से लोहा, सोने में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है।*
>
> **नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

हर साल देश में करीब एक तिहाई हिस्से में सूखा तो औसतन 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ की भयावह तस्वीर सामने आती है। अगर यह असंतुलन खत्म हो जाए तो देश की अपार जल संपदा विनाश की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास की कहानी लिख सकती है। ऐसे में वर्तमान की स्थिति को बदलने और भविष्य के संकटों के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने विश्व जल दिवस के मौके पर 22 मार्च को नदी जोड़ो परियोजना और जल संचयन की दिशा में क्रांतिकारी शुरुआत की है। इसके लिए 'कैच द रेनः जहां भी, जब भी संभव हो वर्षा का जल संग्रह करें' अभियान के साथ-साथ केन-बेतवा लिंक की बहुप्रतीक्षित परियोजना साकार होने जा रही है।

केन-बेतवा लिंक
बुंदेलखंड की नई सुबह

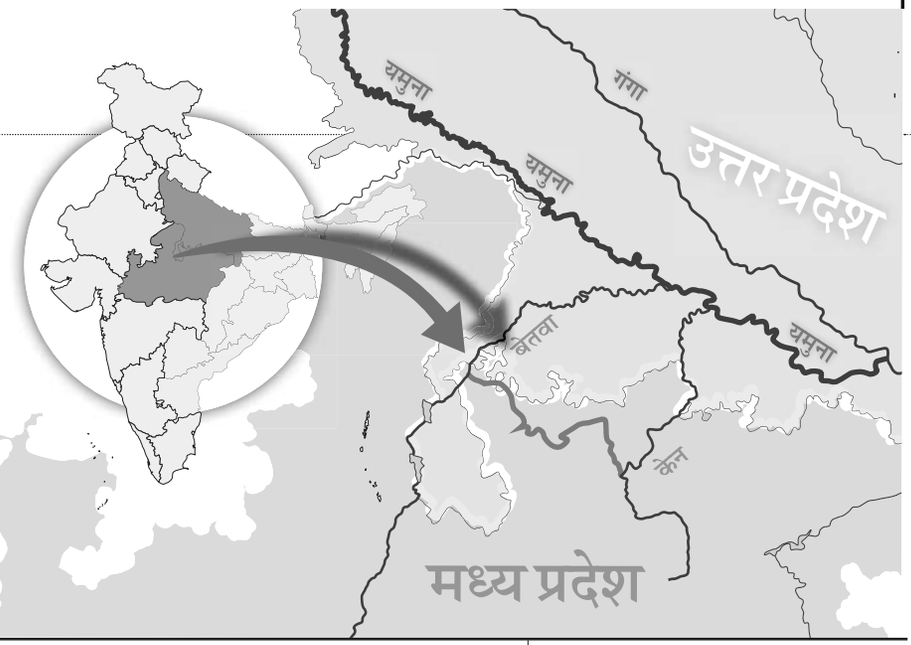

शामिल राज्य
उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश

बुंदेलखंड क्षेत्र के इन जिलों को लाभ

- मध्य प्रदेश
  - छतरपुर
  - पन्ना
  - टीकमगढ़
- उत्तर प्रदेश
  - ललितपुर
  - झांसी
  - बांदा
  - महोबा

केन-बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर की अपनी तरह की पहली परियोजना है। यह सपना जिसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रण लिया है। नदी जोड़ो परियोजना का आगाज बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक से हो गया है। पीएम मोदी के शब्दों में, " अटल जी का एक सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का। केन-बेतवा को जोड़ने का हमने बीड़ा उठाया है। अगर केन-बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जो पानी बहुत नीचे गया है वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा।" नदियों को जोड़ने की प्रधानमंत्री की इस प्रतिज्ञा के पीछे बूंद-बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड के निवासियों को राहत देने का संवेदनशील दृष्टिकोण है।

221 किमी लंबी लिंक नहर से केन का पानी बेतवा नदी तक पहुंचेगा

इसके तहत केन नदी के 2800 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) से ज्यादा बाढ़ के पानी का दौधन बांध द्वारा संचय किया जाएगा। केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किमी लंबी लिंक नहर बनाई जाएगी। इस क्षेत्र में विभिन्न टैंकों, जलाशयों को लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा।

सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा

इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के 9 जिलों- पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन के साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 जिलों- बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को सीधे तौर पर मिलेगा। बुंदेलखंड इलाके की तस्वीर बदलने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना के पूरा होने पर दोनों राज्यों के 13 जिलों की करीब 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।

8.11
लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई मध्य प्रदेश में

2.51
लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई उत्तर प्रदेश में

62 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा

130 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा

जन कनेक्टिविटी से जल कनेक्टिविटी

'कैच द रेन' अभियान को देश भर में 22 मार्च से 30 नवंबर तक की अवधि में भारत के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया है ताकि जन भागीदारी के साथ जल आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का आगाज किया और इसी मौके पर केन-बेतवा लिंक परियोजना के ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। इस कार्यक्रम के बाद जल और जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन कर जल संरक्षण के लिए 'जल शपथ'की भी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, "इन प्रयासों के बीच ये भी चिंता का विषय है कि हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा उतना ही भूजल पर देश की निर्भरता कम होगी। इसलिए 'कैच द रेन' जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी

‘कैच द रेन’ अभियान की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के अंश

> *“जल को लेकर जब हमारी प्रकृति बदलेगी, तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी। हमने बहुत बार सुना है कि अगर सेना के लिए कहा जाता है कि शांति के समय जो सेना जितना ज्यादा पसीना बहाती है युद्ध के समय खून उतना कम बहता है। मुझे लगता है ये नियम पानी पर भी लागू होता है। अगर हम पानी के लिए बारिश से पहले मेहनत करते हैं, योजना बनाते हैं और पानी बचाने का काम करते हैं तो अकाल के कारण जो अरबों-खरबों का नुकसान होता है और बाकी काम रूक जाते हैं, सामान्य मानवी को मुसीबत आती है, पशुओं को पलायन करना पड़ता है, ये सब बच जाएगा। इसलिए जैसे युद्ध में शांति के समय पसीना बहाना ही मंत्र है, वैसे ही जीवन बचाने के लिए वर्षा के पहले जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना उपकार होगा।”*

- हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल उपलब्ध कराएं। हमें पानी बचाने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए।
- मैं तो चाहूंगा अब मनरेगा का एक-एक पैसा, एक-एक पाई बारिश आने तक सिर्फ-सिर्फ इसी काम के लिए लगे। पानी से संबंधित जो भी तैयारियाँ करनी हैं, मनरेगा का पैसा अब कहीं और नहीं जाना चाहिए
- भारत के विकास और आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है, जल कनेक्टिविटि पर निर्भर है।
- आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार पानी की जांच को लेकर इतनी गंभीरता से काम कर रही है। हर गांव में कम से कम 5 प्रशिक्षित महिलाएं पानी की जांच कर रही हैं। Water Governance में हमारी बहनों-बेटियों की भूमिका को जितना अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा, उतना ही बेहतर नतीजे मिलने तय हैं। “आइए मिलकर वर्षा जल संचयन की मुहिम को सफल बनाएं”

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

हैं।” जल कनेक्टिविटी की पहल में बेहतर प्रबंधन और नतीजों के लिए केंद्र सरकार की ओर से तकनीकी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है।

समग्र सोच के साथ जल पर बन रही नीति

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का 4 फीसदी पानी है, जबकि यहां दुनिया की 18 फीसदी आबादी रहती है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक भारत में भूमिगत जल का स्तर तेजी से गिर रहा है। दुनिया भर के कुल भूमिगत जल का 24 प्रतिशत हिस्सा हमारे देश में इस्तेमाल हो रहा है। अपने उपयोग का 40 फीसदी पानी हमें भूजल के जरिए ही मिलता है। कुल उपयोग योग्य जल संसाधनों में भूजल का हिस्सा 432 अरब क्यूबिक घन मीटर है। वहीं, 2018 में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी। जल एक अमूल्य निधि है और जल संरक्षण की महत्ता को समझते हुए 2019 में जल से जुड़े सभी कार्यों का एक मंत्रालय (जल शक्ति मंत्रालय) के अंतर्गत कर दिया गया था। जल संचय को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और दूरदृष्टि को पूर्ण करने के लिए 2019 में जल संकट से जूझ रहे 256 जिलों में जलशक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। हर घर जल और अटल भूजल जैसी कई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों के घर पानी पहुंचा और भूजल स्रोतों का बेहतर प्रबंधन होने लगा।

इस बार जलशक्ति अभियान में विशेषता यह भी है कि इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। मानसून आने में अभी कुछ हफ्तों का समय है, इसलिए प्रधानमंत्री का कहना है कि मानसून के आने से पहले ही टैंकों, तालाबों, कुंओं की सफाई हो, मिट्टी निकालना है तो वो काम हो जाए, वर्षा के पानी के बहकर आने में उसके रास्ते में अगर कहीं कोई रुकावट है तो उसे हटाना है। इस तरह के तमाम कार्यों के लिए पूरी शक्ति लगानी है ताकि पानी संग्रह की क्षमता बढ़े। ●

महिलाओं की प्रेरणा बनीं वेलु, युवाओं की ऊर्जा खुदीराम बोस

आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में मील का ऐसा पत्थर बनने जा रहा है, जहां से अगले 25 साल का 'शताब्दी संकल्प' लेगा। युवाओं की आकांक्षा और 100वीं वर्षगांठ के मौके पर 'नए भारत' का सपना कैसे साकार हो, इसके लिए जरूरी है कि देश स्वतंत्रता संग्राम के उन शूरवीरों की जीवन यात्रा से प्रेरणा ले और राष्ट्र निर्माण की नई राह करे तैयार। ऐसे में 'न्यू इंडिया समाचार' पेश कर रहा है प्रमुख सेनानियों और गुमनाम नायकों की संघर्ष गाथा

जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं, जहां करोड़ों-करोड़ लोगों ने सदियों तक आज़ादी की एक सुबह का इंतज़ार किया, तब ये अहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक और गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा, स्वाधीनता संग्राम की परछाई और आजाद भारत की गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। लेकिन देश के स्वाधीनता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन और संघर्ष हैं जो देश के सामने उस रूप में नहीं आए जैसे आने चाहिए थे। जबकि हरेक संग्राम अपने आप में भारत की असत्य के खिलाफ सत्य की सशक्त घोषणाएं हैं, स्वाधीन स्वभाव के सबूत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, "ये संग्राम इस बात का भी साक्षात प्रमाण हैं कि अन्याय, शोषण और हिंसा के खिलाफ भारत की जो चेतना राम के युग में थी, महाभारत के कुरुक्षेत्र में थी, हल्दीघाटी की रणभूमि में थी, शिवाजी के उद्घोष में थी, वही शाश्वत चेतना, वही अदम्य शौर्य, भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर समाज ने आजादी की लड़ाई में अपने भीतर प्रज्वलित करके रखा था।"

उनका मानना है कि आजादी के इतिहास में कोल आंदोलन या खासी आंदोलन या संथाल क्रांति, कछोहा कछार, नागा संघर्ष हो या कूका आंदोलन, भील आंदोलन हो या मुंडा क्रांति, संन्यासी आंदोलन हो या रमोसी संघर्ष, कित्तूर, त्रावणकोर आंदोलन, बारडोली, चंपारण सत्याग्रह, संभलपुर, चुआर, बुंदेल संघर्ष, ऐसे कितने ही संघर्ष और आंदोलनों ने देश के हर भूभाग को, हर कालखंड में आजादी की ज्योति से प्रज्वलित रखा। सिख गुरू परंपरा ने देश की संस्कृति, रीति-रिवाज की रक्षा के लिए नई ऊर्जा-प्रेरणा दी, त्याग और बलिदान का रास्ता दिखाया। इसलिए उन संघर्षों को बार-बार याद करना चाहिए।

अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम करने वाली रानी

तमिलनाडु की वेलू नाचियार वो पहली महारानी थीं, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। रामनाथपुरम की रहने वाली वेलू विवाह के बाद शिवगंगा रियासत की रानी बनी थीं। 1772 में, अंग्रेजों ने शिवगंगा पर कब्जा करने के लिए उस पर हमला किया और वेलू के पति ने उनसे बातचीत करने के लिए दूत भेजे। हालांकि, ब्रिटिश सेना ने हमला कर वेलू के पति की हत्या कर दी, जिसके बाद वह अपने बदला लेने के लिए कृत संकल्पित हो गई। उसे मारुड़ ब्रदर्स, कई बड़े सरदारों और वफादारों सहित अपने अंगरक्षकों के नेता उदयाल का संरक्षण भी प्राप्त था। बहादुर वेलु ने महिलाओं की एक और बटालियन खड़ी की और उसे उदयाल रेजिमेंट नाम दिया। इसकी कमान उनकी वफादार कुइली ने संभाली थी। कुइली ने कुछ महिला छापामारों को अभियान पर लगाया और जब खाड़ी में अंग्रेजों ने उनको पकड़ा तो उसने गोला बारूद भंडार में घुसकर आग लगा दी। इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि सबसे पहले मानव बम का इस्तेमाल उन्होंने ही किया था। वेलु नचियार ने अंग्रेजों के कब्जे से शिवगंगा को मुक्त कराया और वह वहां की महारानी बन गई और दस वर्षों तक शासन किया। 1947 में रियासतों के विलय होने तक शिवगंगा पर उनके परिवार का ही शासन रहा। भारत सरकार ने 2008 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया।

शहीद होकर आजादी की अलख जगाने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी

खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक हैं जिन्हें अंग्रेजों ने 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर की जेल में फांसी दे दी थी। खुदीराम बोस का जन्म 3 सितंबर 1889 को अविभाजित बंगाल के मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। बाल्यकाल में ही अपने माता-पिता को खो देने वाले बोस का लालन-पालन उनकी बड़ी बहन ने किया था। 1905 में 'बंग-भंग' यानि बंगाल विभाजन के बाद वह देश की आजादी के लिए आंदोलन में कूद पड़े और सत्येन बोस के नेतृत्व में अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। बोस को एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस सिलसिले में वह बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। एक दिन मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया। संयोग से उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि एक दूसरे अंग्रेज़ अधिकारी की पत्नी और बेटी थीं। हमले में उन दोनों की मौत हो गई। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस उनके पीछे पड़ गई और आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी

योग्यता की परीक्षा

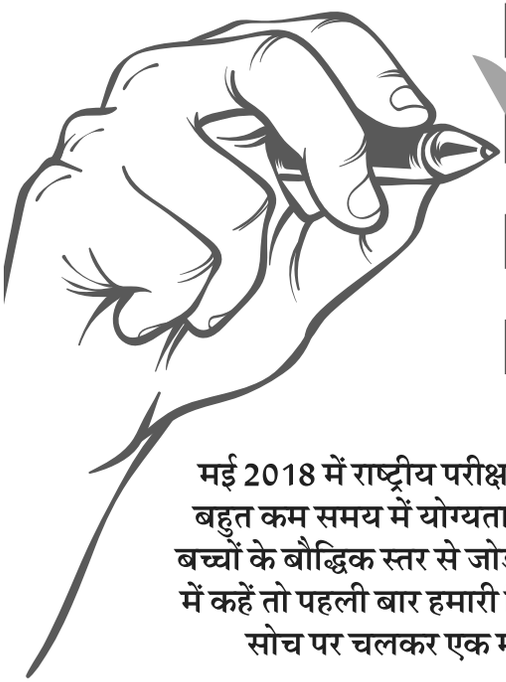

मई 2018 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के रूप में ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था अस्तित्व में आई, जिसने बहुत कम समय में योग्यता और क्षमता के मूल्यांकन की दशा-दिशा बदल दी है, ताकि परीक्षा के स्तर को बच्चों के बौद्धिक स्तर से जोड़ उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल ज्ञान से लैस किया जा सके। आसान शब्दों में कहें तो पहली बार हमारी शिक्षा व्यवस्था को रैंकिंग के बजाय योग्यता पर आधारित बनाने और वैज्ञानिक सोच पर चलकर एक मजबूत ढांचा खड़ा करने की शुरुआत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से ही होती है

प्रमोद कुमार पासवान ने बीते वर्ष ही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) क्वालिफाइ की है। वे 4 साल पहले भी नेट की परीक्षा दे चुके हैं, तब इसका आयोजन सीबीएसई के हाथों में था। भारत में प्रवेश परीक्षा को पूरा ढांचा बदलने का श्रेय एनटीए को देते हुए प्रमोद कहते हैं, "पहले परीक्षा में ऐसे सवाल आते थे जो किताब से होते थे और पढ़ा-पढ़ा सा लगता था। लेकिन अब नए तरह से समसामयिक सवाल आते हैं, जो सैद्धांतिक नहीं होकर व्यावहारिक ज्ञान का अहसास कराते हैं।" प्रमोद की तरह ही नेट परीक्षा देने वाले मुद्रिका प्रसाद मंडल कहते हैं, "ऑफलाइन परीक्षा में पूरा दिन बर्बाद होता था, लेकिन अब ऑनलाइन परीक्षा से महज तीन घंटे में पेपर हो जाता है। ओएमआर शीट में गोला लगाने में अब आसानी हो गई है क्योंकि पेपर सबमिट करते वक्त तक गोला बदलने का विकल्प रहता है जो ऑफलाइन में नहीं था।" प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले इन छात्रों का कहना है कि एनटीए के परीक्षा पैटर्न से कागज की बचत पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहतर है और सैद्धांतिक सवालों की बजाए व्यावहारिक विषयों पर सवाल इस परीक्षा की अहमियत को बढ़ाता है क्योंकि ज्ञान की असली पहचान इसके जरिए हो पा रही है।

अक्सर आपने यह देखा-सुना होगा कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन माता-पिता या अन्य परिस्थितियों ने उसे इंजीनियरिंग की दिशा में धकेल दिया। नतीजा होता है कि प्रतियोगी परीक्षा के दौरान मेरिट लिस्ट में उस बच्चे की रैंकिंग ऐसी नहीं आ पाती कि मनपसंद संस्थानों में अपनी इच्छा के विषय चुन सके। ऐसे में बच्चा या तो फिर से तैयारी करता है या फिर किसी दूसरे विषय की तरफ मुड़कर जीवन का लक्ष्य बदल लेता है। लेकिन आजाद भारत में क्षमता की सही पहचान और छात्र के भीतर से उसकी योग्यता को निकालकर उसका भरपूर लाभ उठाने की वैसी पहल कभी नहीं हुई, जैसी दुनिया के विकसित देशों में होती है। इस विषय का व्यापक अध्ययन और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद नवंबर 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक ऐसी परीक्षा एजेंसी के गठन को मंजूरी दी, जो खुद अपने संसाधन जुटाकर बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बाहर निकालकर उसे सही जगह पर स्थापित करने का काम करे। इस दिशा में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) लगातार काम कर रही है। मई 2018 में संस्था के अस्तित्व में आने के बाद से महज तीन साल में ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से छात्रों की सही क्षमता का आकलन करने में यह वरदान साबित हो रही है। एनटीए सिर्फ परीक्षा के जरिए ही मूल्यांकन नहीं कर रही, बल्कि परीक्षा के दौरान सवाल हल करने के छात्रों के तौर-तरीकों, समय, समझ आदि का आकलन करके संबंधित बोर्ड और विशेषज्ञों को भी जरूरी बदलाव का सुझाव दे रही है ताकि परीक्षा के साथ-साथ शिक्षा की व्यवस्था का मानक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का बने।

दरअसल भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रोफेशनल कोर्सों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा एक पूर्व निर्धारित पैटर्न पर ही कराई जाती थी। इन प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक ज्ञान के परीक्षण का अभाव था।

> ***जो लोग साल का सोचते हैं अनाज बोते हैं, जो दस साल का सोचते हैं वो फलों का वृक्ष बोते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। मतलब उसको शिक्षित, संस्कारित, जीवन को तैयार करना। हमारी शिक्षा प्रणाली को जीवन निर्माण के साथ जीवंत बनाना है।***
>
> **नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

60 लाख परीक्षार्थी बैठते हैं हर साल विभिन्न संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में

एनटीए ने कम किया भार; यूजीसी, सीबीएसई और एआईसीटीई का ध्यान अब सिर्फ शैक्षणिक कार्यक्रमों पर

अब उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं का पैटर्न अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार करने पर ध्यान दिया गया है, जबकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति भारतीयों को क्लर्क बनाने तक सीमित थी। तब मैकाले की सोच थी कि थोड़ी-बहुत अंग्रेजी सिखाकर उसे अंग्रेजी हुकुमत से बातचीत करने भर योग्य बनाया जाए। तबसे लेकर बीते कुछ साल तक किसी भी सरकार ने इस शिक्षा पद्धति में बदलाव लाकर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की कोई पहल नहीं की। लेकिन अब उच्च शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तरीय बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का ही नतीजा है कि भारत में पहली बार कौशल के साथ योग्यता की सही पहचान के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे संस्थान की स्थापना की गई और उनका यही दृष्टिकोण 34 साल बाद आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार बना है। हालांकि प्रवेश परीक्षाओं की पूरी प्रणाली को बदलने का यह सफर इतना आसान नहीं था। एनटीए के निर्माण के पीछे कई और भी कारण थे।

अतिरिक्त जिम्मेदारी

आजादी के बाद जब भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की तैयारी शुरु हुई तो कई ऐसे नियामक या एजेंसियों का गठन किया गया जिनको उनके एक विशेष दायरे में रहकर काम करना था। जैसे-उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी), स्कूली शिक्षा के लिए 1962 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन आदि। इन सब संस्थाओं का कार्यक्षेत्र निर्धारित था। लेकिन बावजूद इसके इनके जिम्मे कई और भी काम थे। जैसे- असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता परीक्षा पहले यूजीसी और फिर सीबीएसई के जिम्मे आ गई। ऐसी तमाम अलग-अलग पात्रता परीक्षाओं के लिए अलग संस्था जिम्मेवार थी। इस तरह से इन संस्थाओं के खुद के काम पर भी असर पड़ रहा था।

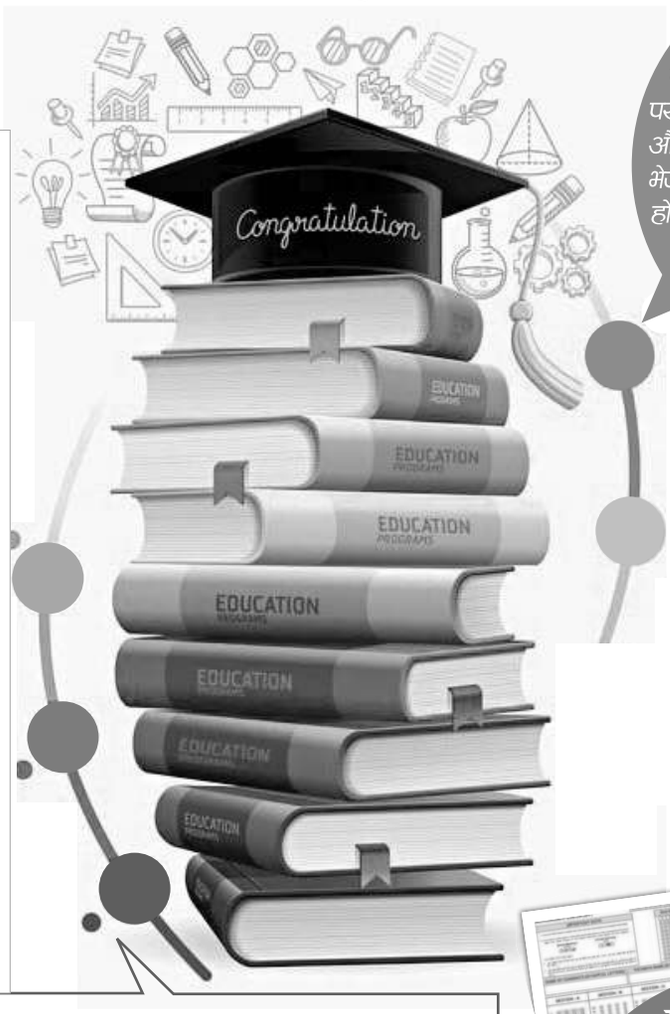

परीक्षा से मूल्यांकन तक लंबा वक्त

सभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होती थीं। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका इकट्ठी की जातीं और फिर इन्हें परीक्षा कराने वाली एजेंसी तक भेजने में वक्त लगता था। इसके बाद मूल्यांकन होता। इस पूरी प्रक्रिया के बाद अकेले परिणाम घोषित करने में ही कभी-कभी महीना भर से ज्यादा लग ज्यादा था। इसलिए सभी परीक्षाएं साल में सिर्फ एक बार ही हो पाती थीं।

भारी संसाधनों की आवश्यकता

परीक्षा ऑफलाइन मोड में होने की वजह इसकी तैयारी, प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा कराने और फिर मूल्यांकन कर परिणाम घोषित करने तक की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भारी संसाधनों की जरूरत होती थी। प्रवेश परीक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी को निभाने के लिए सीबीएसई और एआईसीटीई जैसे संस्थाओं को अपने पूरे संसाधन इसमें झोंकने होते थे, इससे इनके खुद के काम प्रभावित होते थे।

मानवीय भूल के साथ गलती की गुंजाइश

बोझिल प्रक्रिया के चलते मानवीय भूल सहित हर स्तर पर गलती की कोई न कोई गुंजाइश बनी रहती थी। जैसे- उत्तर पुस्तिका में गलत रोल नंबर भर जाना। ओएमआर शीट में गलत जगह या फिर सही से गोले न लगा पाने के कारण मूल्यांकन न हो पाना। साथ ही ओएमआर शीट में परीक्षा के बाद भी जान-बूझकर गड़बड़ी होने की गुंजाइश भी बनी रहती थी।

रैंकिंग को वरीयता। *यह हमारी शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी कमी रही है। देश के सभी क्षेत्रों के छात्रों को एक जैसा प्रश्नपत्र मिलता था। मूल्यांकन के बाद रैंकिंग और फिर एडमिशन होता था। लेकिन छात्र उस प्रश्नपत्र के बारे में क्या सोचते हैं, उनके लिए वो कैसा है ऐसा कोई आंकड़ा या फीडबैक नहीं होता था। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं मान लीजिए कि अलग-अलग बोर्ड और प्रदेशों के दो छात्रों ने आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र हल किया। दोनों में से किस छात्र को कौन सा प्रश्न आसान लगा। उसने किस प्रश्न को हल करने में कितना समय दिया। ऐसा कोई अध्ययन पहले संभव नहीं था। इन प्रवेश परीक्षाओं में वह एकरूपता नहीं थी, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर इसे सबसे अलग खड़ा कर पाए।*

इन्हीं सब कारणों से 1986 की शिक्षा नीति में एनटीए जैसी एक संस्था की परिकल्पना रखी गई। इसके बाद वर्ष 2010 में फिर एक बार ऐसे आयोग का विचार सामने आया जो पूरे भारत में सभी तरह के उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए जिम्मेदार हो। जिसका काम विश्वस्तरीय शोध के साथ एक तंत्र खड़ा करना हो, ताकि छात्रों की प्रतिभा को सही मुकाम मिल सके। इस मुकाम के लिए रास्ता दिखाने का काम भी इसी निकाय के भरोसे हो। लेकिन यह विचार ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा। वर्ष 2014 में फिर इस दिशा में काम करने के प्रयास शुरू हुए और आखिर 10 नवंबर 2017 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860 के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए बनाने की घोषणा की गई। मई 2018 में इसका पंजीकरण किया गया। दिसंबर 2018 में पहली बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा(नेट) का आयोजन एनटीए द्वारा किया गया। अब एक वर्ष में ही 14 तरह की प्रवेश परीक्षा, फेलोशिप परीक्षा, विश्वविद्यालय पात्रता परीक्षा का आयोजन एनटीए द्वारा किया जा रहा है। दो वर्ष में ही करीब 1.23 करोड़ परीक्षार्थी एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भागीदारी कर चुके हैं। पहली बार भारत में पूरी तरह पेन और पेपरलेस परीक्षा की शुरुआत करने का श्रेय एनटीए को ही जाता है। हम कह सकते हैं भारत की शैक्षणिक प्रणाली में सुधार की सबसे बड़ी शुरुआत यहीं से होती है।

एनटीए का उद्देश्य : प्रवेश परीक्षाओं में विश्वस्तरीय मानक स्थापित करना...

एनटीए की घोषणा के समय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में देश की शिक्षा व्यवस्था संभालने वाले प्रकाश जावडेकर कहते हैं, "एनटीए की स्थापना प्रतियोगी परीक्षाओं को ठीक ढंग से आयोजित कराने का अद्भुत रास्ता है। तकनीक की सहायता से पूरे देश में एक साथ परीक्षा होती है और उससे परीक्षा में गड़बड़ी की संभावना भी नहीं रहती है। परीक्षा की प्रणाली और निगरानी एनटीए के माध्यम से इतनी चुस्त हो गई है कि देश और दुनिया के सामने एक मिसाल बन गई है।" प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी से लेकर परीक्षा कराने और मार्किंग यानी मूल्यांकन की पूरी जिम्मेदारी एनटीए को दी गई है। इसे एनटीए की सफलता ही कहा जाएगा कि आज की तारीख में 12 तरह की प्रवेश परीक्षाओं के साथ दो विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा भी एनटीए द्वारा कराई जाती है और वो भी बिल्कुल त्रुटिरहित।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) समाज के समक्ष आ रही शिक्षा चुनौतियों जैसे साक्षरता स्तर और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए गुणवत्ता बढ़ाने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अंतरराष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों की तर्ज पर पहली बार हर परीक्षा के

> ***एनटीए जैसी संस्था की स्थापना की बात 1986 की शिक्षा नीति में की गई थी। इस सरकार ने एनटीए को 2018 में बनाकर एक ऐसे कार्य को संपादित किया है जो कि पिछले 32 वर्षो तक नहीं हो सका था। एनटीए ने पिछले केवल 2 वर्षो में ही करीब 45 परीक्षाएं करवाई जिनमें 1.23 करोड़ परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। इन परीक्षाओं में करीब 33 भाषाएं, 13 परीक्षा माध्यम, एवं 450 विषय सम्मिलित हैं। एनटीए, अंतरराष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उपयोग किए जाने वाले साइकोमेट्रिक सिद्धांतों के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करती है।***
>
> **डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री**

बाद परीक्षा पैटर्न पर आधारित डेटा का साइकोमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है। यानी कोई परीक्षा देने वाला छात्र पूछे गए प्रश्नों को किस तरह हल करता है? किस प्रश्न पर उसे कितना समय लगता है? भाषा माध्यम अलग होने की वजह से अनुवाद सही हुआ या नहीं? जैसे- किसी प्रश्न को अंग्रेजी की बजाय हिंदी में समझने में ज्यादा समय तो नहीं लग रहा? अलग-अलग क्षेत्र या बोर्ड के हिसाब से इसका तुलानात्मक अध्ययन एनटीए के विशेषज्ञ करते हैं। इसका पूरा डेटा तैयार किया जाता है। इसे संबंधित बोर्ड या शिक्षा विभाग के साथ साझा किया जाता है। इसके आधार पर शिक्षा पद्धति में सुधार या पढ़ाने के तरीके में बदलाव किया जाए जैसे दूसरे उपाय किए जा सकते हैं। साइकोमेट्रिक डेटा का इस्तेताल कर शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके

से लेकर पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने में किया जाता है। साथ ही, एनटीए के विशेषज्ञों को भविष्य में प्रश्न पत्र को और बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। यानी साइकोमेट्रिक एनालिसिस जैसी व्यवस्था के चलते हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को गहराई से अध्ययन करने का मौका मिलता है, वो छात्रों के डेटा के ही माध्यम से। **एनटीए के एजेंडा में शामिल इन 3 बिंदुओं को हमें समझना चाहिए...**

मूल्यांकन में सुधार

मूल्यांकन की पुरानी पद्धतियों के बजाय त्रुटिरहित ऑनलाइन मूल्यांकन हो साथ ही, इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से भविष्य के लिहाज से इसे और बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अपनी स्थापना के बाद से ही एनटीए प्रवेश परीक्षाओं के मूल्यांकन पर लगातार शोध करता रहा है।

रिसर्च पॉलिसी बनाना

आम जन से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च के साथ मूल्यांकन का काम भी एनटीए करता है। यही नहीं, दुनिया भर में नीतिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग कैसे किया जा सकता है, यह भी एनटीए के एजेंडे में शामिल है।

सबके लिए समावेशी

प्रवेश परीक्षाओं को दिव्यांगों के साथ सभी परीक्षार्थियों के अनुकूल और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए एनटीए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर परीक्षा में छात्रों के हित में ऐसे कदम उठाए जाते हैं।

छात्रों के लिए सहज हुई परीक्षा

हम एनटीए को भले ही देश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी कदम बता रहे हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए क्या बदला और उन्हें नई व्यवस्था का क्या लाभ हुआ? कैसे हर साल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले 60 लाख से अधिक छात्रों के लिए एनटीए ने नई व्यवस्था लागू की। आइए इसे समझते हैं।

साल में दो बार परीक्षाएं होने से विकल्प चुनने का मौका

आईआईटी सहित देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट(नीट) जैसी परीक्षाएं पहले साल में सिर्फ एक बार होती थीं। यानी लंबे समय से इनमें एडमिशन के लिए मेहनत कर रहे छात्रों को पूरे साल में सिर्फ एक मौका मिलता था। चयन न होने की स्थिति में छात्र तनाव में आ जाते और फिर दोबारा से पूरे साल उन्हें तैयारी करनी होती थी। लेकिन, एनटीए अब ऑनलाइन मोड के जरिए इन परीक्षाओं को साल में दो बार आयोजित करता है। दोनों परीक्षाओं में से जिसमें भी छात्र के नंबर ज्यादा होते हैं, उसका परिणाम अंतिम माना जाता है। इससे छात्रों का समय और पैसा

बचा साथ ही, एक प्रयास में असफल रहने पर पूरे साल तैयारी का तनाव कम हुआ है।

लीकेज प्रूफ सिस्टम से प्रतिभा को सही मुकाम

पहले सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होती थीं। यानी छात्रों को प्रश्नपत्र और उसके साथ एक ओएमआर शीट दी जाती थी। ओएमआर शीट में गोले बॉल पेन से भरकर प्रेक्षक के पास जमा करना होता था। इस सिस्टम में 3 कमियां थीं। एक तो गोले भरते समय मानवीय त्रुटि की संभावना रहती थी, जिसे बाद में सुधारा नहीं जा सकता था। दूसरी ओर, परीक्षा खत्म होने के बाद ओएमआर शीट में गड़बड़ी की गुंजाइश बनी रहती थी। तीसरा, पेपर लीक होने की भी कई शिकायतें पहले मिलती रही हैं। लेकिन अब परीक्षा ऑनलाइन होने से यह पूरा सिस्टम लीकेज प्रूफ हो गया है। एनटीए के विशेषज्ञों द्वारा तैयार प्रश्नपत्र तय समय पर एनक्रिप्टेड फार्मेट

बातचीत

सही प्रतिभा पहचानना और उसे उचित मुकाम दिलाना, यही हमारा काम : विनीत जोशी

भारत में प्रवेश परीक्षा को लेकर कभी इतना सोचा ही नहीं गया। यही कारण है कि पहले छात्र जो परीक्षा देते थे, वो एक निर्धारित पैटर्न पर होती थीं। इस तरह की परीक्षा से न ही प्रतिभा को सही मौका मिल पाता था और न ही पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते थे। हम इस मामले में दूसरे देशों से कहीं पीछे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के स्तर के साथ इस पूरे ढर्रे को अब बदल दिया है। 'न्यू इंडिया समाचार' के सलाहकार संपादक संतोष कुमार से एनटीए के डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी ने एनटीए की कार्यशैली से लेकर इसकी जरूरत और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत बातचीत की। पढ़िए उसके अंश...

एनटीए बनाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है?

इसके पीछे का मकसद एक ऐसी संस्था बनाना है, जो भारत में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मापदंड स्थापित कर सकें। हम हर बार परीक्षा के बाद मिले डाटा का विश्लेषण करते हैं। ये देखते हैं कि छात्रों को किस प्रश्न में कौन सी समस्या आ रही है? किस बोर्ड या क्षेत्र के छात्रों को कोई प्रश्न आसान या कठिन लगा? किसी प्रश्न के अनुवाद के कारण छात्रों को इसे समझने में समस्या तो नहीं आई। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई प्रश्न अंग्रेजी में आसानी से समझ में आया, लेकिन हिंदी प्रश्नपत्र में उसका अनुवाद ठीक नहीं था। दूसरे देशों में इस तरह से काम होता है। अब एनटीए के जरिए हम ऑनलाइन परीक्षा के बाद इस तरह मिले डाटा का एनालिसिस करते हैं। भविष्य में दोबारा उस परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। यह डाटा एजुकेशन बोर्ड के साथ साझा किया जाता है। इसके माध्यम से पढ़ाई के पैटर्न को और बेहतर बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है।

शुरुआत में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा?

दिसंबर 2018 में जब हम पहली बार नेट की ऑनलाइन परीक्षा कराने जा रहे थे, तब इस पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। कुछ बातें सही भी थीं, क्योंकि वर्तमान में तो हम स्कूल स्तर से ही कंप्यूटर बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। ऐसे में जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और उन्हें कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है, वो कैसे परीक्षा देंगे? लेकिन हमने इसके लिए हर शहर में कुछ निर्धारित केंद्र बनाए, जहां जाकर वो परीक्षा से पहले इसकी प्रैक्टिस कर सकते थे। एप भी बनाया जिसके जरिए प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता था। हम सहीं दिशा में आगे बढ़े इसलिए सफल हो पाए। आज एनटीए की वेबसाइट पर हर परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र हल करने से लेकर मॉक टेस्ट के जरिए प्रैक्टिस की सुविधा हमने दी हुई है, ताकि कोई भी ऑनलाइन परीक्षा के दौरान असहज न हो।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एनटीए की क्या भूमिका है?

जहां तक प्रवेश परीक्षाओं में सुधार में एनटीए की भूमिका का सवाल है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए एक परीक्षा का जिक्र है। यह परीक्षा दो भागों में होगी। पहला- एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रुचि आधारित और दूसरा- विषय आधारित परीक्षा। नए शैक्षणिक सत्र (2021-22) में उच्च शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हो सकता है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर सिर्फ चर्चा ही हुई है, अंतिम निर्णय होना बाकी है।

पुराने सिस्टम में कौन सी खामियां थीं जो एनटीए से दूर हुई?

पहले जब प्रश्न पत्र तैयार होते थे जब एनालिसिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। यही कारण था, कि अक्सर सुनने में आता था कि इस बार एग्जाम बहुत कठिन था या इस बार तो इतना आसान हुआ। लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम के चलते पूरा डाटा हमारे पास रहता है। इसलिए प्रश्न पत्र निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सेट किए जाते हैं। इसके अलावा पहले बहुत ज्यादा संसाधन परीक्षा कराने में लगते थे। यह पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी। सीबीएसई का चेयरमैन रहते हुए मैंने इसे बहुत करीब से देखा है, वहां एक रिजल्ट तैयार करने में महीना भर लग जाता था। यहां हफ्ते भर में ही हम रिजल्ट तैयार कर लेते हैं। पहले एक विषय का एक्सपर्ट एक ही प्रश्नपत्र के लिए काम करता था। क्योंकि उसके पास और भी कई काम होते थे। एनटीए में अब हमारे पास हर विषय के एक्सपर्ट हैं, हम कई प्रवेश परीक्षाओं पर उनसे काम करा सकते हैं। इसी का नतीजा है कि हम कई परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित करा रहे हैं। इस साल हम 25 परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं।

छात्रों को किस तरह से इसका फायदा पहुंचा है?

ऑनलाइन टेस्ट होने के चलते अब हम साल में दो बार एग्जाम करा रहे हैं। जेईई तो इस साल चार बार होगा। विकल्प मिलने से छात्रों का तनाव कम हुआ है। एक एग्जाम में अगर वो ठीक नहीं कर पाया तो अगले पर ध्यान दे सकते है। एग्जाम के बाद अब यह चिंता उन्हें नहीं रहती, कि मैंने ओएमआर शीट में गलत जगह तो गोला नहीं बना दिया या मेरा रोल नंबर तो सही लिखा है। कुल मिलाकर हमने उनके तनाव को कम करने का काम किया है। प्रश्न पत्र तैयार करने का पैटर्न भी मैंने आपको बताया है, यह अब छात्रों के हित को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। पर्सेंटाइल को ध्यान में रखकर रैंक तय की जाती है। इससे सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो यह कि अब हर छात्र की योग्यता की पहचान कर सकते हैं, वो भी सबको समान अवसर के साथ।

भविष्य में एनटीए के विस्तार की क्या संभावना है?

चीन में कॉलेजों में दाखिले के लिए गावकाओ परीक्षा में करीब 1 करोड़ परीक्षार्थी बैठते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन यह केवल कुछ भाषाओं में होती है। जबकि एनटीए द्वारा आयोजत नीट परीक्षा में 16 लाख परीक्षार्थियों को हमने 16 भाषाओं में प्रश्न पत्र दिए हैं। वैश्विक मानकों के आधार के साथ हम पूरे देश की प्रतिभाओं को समान अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इससे आगे बढ़कर जल्द ही एनटीए परीक्षा आयोजित करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी होगी। हम लगातार यह कोशिश कर रहे हैं प्रश्न पत्र इस तरह से तैयार हों कि छात्रों की सही योग्यता सामने आ सके और हमारी शिक्षा व्यवस्था से परीक्षा तक वैज्ञानिक सोच पर आधारित एक शानदार सिस्टम खड़ा हो जाए।

में सीधे परीक्षार्थी के कंम्प्यूटर सिस्टम पर खुलता है। परीक्षार्थी इसमें सही जवाब को टिक लगाकर सबमिट करता है और जरूरत पड़ने पर इस जवाब में बदलाव भी कर सकता है। परीक्षा खत्म होने के बाद पूरा डाटा सीधे एनटीए के सर्वर में जाकर जमा हो जाता है।

हर बारीकी को ध्यान में रखकर तैयार प्रश्न पत्र

किसी भी परीक्षा का प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए एनटीए के पास विशषज्ञों की एक टीम है। पिछली परीक्षा से मिले साइकोमेट्रिक एनालिसिस से मिले डाटा और पैटर्न का विश्लेषण कर विशेषज्ञ नई परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। प्रश्नपत्र तैयार करते वक्त हर बारीकी का ध्यान रखा जाता है, जैसे-

परीक्षा कौन और किस उद्देश्य से लेगा?
किस स्किल/ज्ञान का आकलन किया जाएगा?
परीक्षार्थी अपने ज्ञान का उपयोग कैसे कर पाएंगे?
टेस्ट कितना लंबा होना चाहिए?
टेस्ट कितना कठिन होना चाहिए?

इसके बाद तैयार प्रश्नपत्र की गहनता के साथ समीक्षा की जाती है, जरूरी संशोधन किए जाते हैं। इसके बाद यह प्रश्न पत्र छात्रों के पास पहुंचता है। इसके बाद भी हर प्रश्न और उसके तय उत्तर को लेकर गहन समीक्षा की जाती है। प्रश्न पत्र में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर छात्र की प्रतिभा के सही स्तर का मूल्यांकन उचित तरीके से हो सके।

अब समय का हो रहा सदुपयोग

परीक्षा ऑनलाइन होने से जहां सिस्टम में लीकेज की संभावना खत्म हुई है, वहीं परीक्षा लेने वाली एजेंसी और छात्र दोनों के ही समय की भी बचत हुई है। मूल्यांकन में त्रुटि की संभावना खत्म हुई है तो अब छात्रों को भी परिणाम के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होता है।

अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्थापना

एनटीए द्वारा आयोजित हर परीक्षा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो इसका ध्यान रखा जाता है। हर विषय के विशेषज्ञों को इसके लिए साथ जोड़ा गया। दूसरे देशों में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्ययन के साथ वहां की एजेंसियों के विशेषज्ञों से भी संवाद किया जाता है। इस प्रक्रिया के जरिए समय-समय पर प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया जाता है।

वर्ष 2014 के बाद से ही केंद्र सरकार का प्रयास है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में कौशल और व्यवहारिक ज्ञान के साथ वैज्ञानिक ज्ञान का समावेश हो। इसीलिए एनटीए के जरिए जो शुरुआत वर्ष 2018 में की गई, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब केंद्र सरकार ने 34 साल के लंबे इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का खाका देश के सामने रखा है। ●

विकास को गति देने के लिए संसाधन जुटाने की नई पहल

आर्थिक विकास को रफ्तार देकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश के लिए धन जुटाने के नए स्रोतों पर अमल शुरू किया, ताकि विकास का काम रूके ना और राष्ट्र की प्रगति हो सुनिश्चित

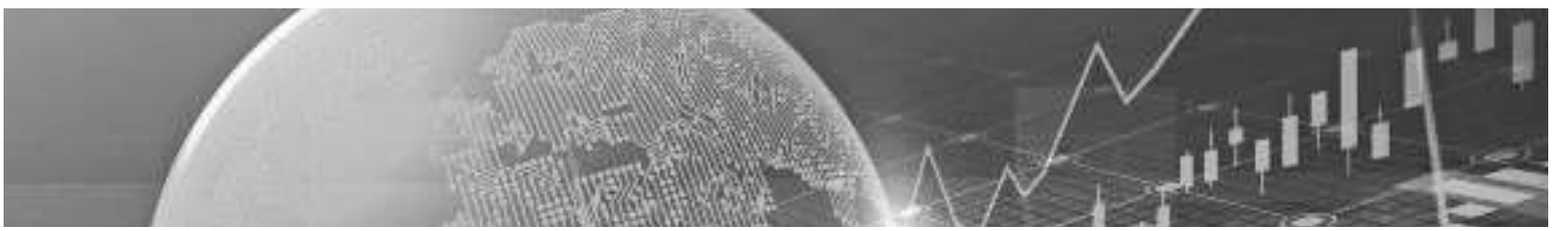

फैसला: आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में इंफ्रा-फाइनेंसिंग का सुदृढ़ीकरण करने के लिए विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) की स्थापना को मंजूरी।

पृष्ठभूमि और प्रभाव

- डीएफआई दीर्घकालिक फंड जुटाने में मदद करेगा, इसे इस साल के आम बजट से शुरुआती राशि मिलेगी, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने आम बजट के दौरान की थी।
- इस वर्ष के लिए 20 हजार करोड़ रूपये का पूंजी निवेश, अगले 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ रु. तक फंड जुटाने की उम्मीद है। प्रारंभिक अनुदान 5 हजार करोड़ रुपये का होगा और अतिरिक्त अनुदान में भी बढ़ोतरी होगी।
- डीएफआई इंफ्रा फाइनेंसिंग को मजबूत करने में सहायक होगा और गति देने का काम करेगा। मांग पुनरुद्धार और नए रोजगार सृजन से आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

फैसला: आर्थिक विकास के लिए पॉवर इंफ्रा को सशक्त करने के लिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए संशोधित अनुमानों को मंजूरी।

पृष्ठभूमि और प्रभाव:

- 9129.32 करोड़ रुपये का संशोधित लागत अनुमान, इस योजना की पूरी लागत का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना को पावरग्रिड के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है और इस साल दिसंबर तक इसे चरणबद्ध तरीके से चालू करने का लक्ष्य है।
- इससे प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में वृद्धि होगी और योजना राज्यों के आर्थिक विकास में योगदान देगी।
- स्थानीय लोगों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

फैसला: हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी।

पृष्ठभूमि और प्रभाव: बीमार उपक्रम जो चालू स्थिति में नहीं है और पर्याप्त आय नहीं कर पा रहे हैं, उसे बंद करने से लगातार बढ़ रहे सरकारी खर्च में कमी आएगी। वित्त वर्ष 2015-16 से कॉरपोरेशन लगातार घाटे में चल रहा है और अपने संचालन तक के खर्च की भी आमदनी को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसे घाटे से उबार पाना संभव नहीं है, इसलिए इसे बंद करना जरूरी है। इस कॉरपोरेशन में 59 स्थायी कर्मचारी और 6 मैनेजमेंट प्रशिक्षु हैं, जिन्हें वीआरएस का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा। ●

टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में आगे बढ़ रहा भारत

कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में भारत सतर्कता के साथ हर वह कदम उठा रहा है जो जन-जीवन और देश की व्यवस्था को सुचारू बनाए हुए है। दुनिया का सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए भारत अब 45 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की बड़ी पहल के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की ऐसी व्यवस्था बना रहा है, जिसकी मुरीद हो रही है दुनिया

जांच, निगरानी और उपचार (टी-3) की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है तो टीकाकरण अभियान को भी विस्तार देते हुए गति तेज कर दी गई है। देश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब 45 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। अभी तक सिर्फ गंभीर श्रेणी में शामिल 45 से अधिक उम्र के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था। इसके लिए बाकायदा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिखाना पड़ रहा था। केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि देश में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और दोनों वैक्सीन प्रभावी हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन टीका लगवाकर इसका प्रमाण दिया है। कोरोना से जंग में वैज्ञानिकों-विशेषज्ञों की सलाह को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार कई नीतिगत बदलाव भी कर रही है। इसी कड़ी में प्रतिरक्षण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (नटागी) और वैक्सीन पर राष्ट्रीय उच्च स्तरीय प्रशासनिक समूह (नेगवैक) की सलाह पर कोविशील्ड टीके के लिए 4-6 सप्ताह में दूसरा डोज लेने की अवधि को अब बढ़ाकर 4 से 8 सप्ताह कर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के अभूतपूर्व पहल का ही

वैक्सीन के नए प्रावधान जो जानना है जरूरी

- कोवीशील्ड वैक्सीन के दो डोज के बीच का अंतराल 4-6 सप्ताह से बढ़ाकर 4-8 सप्ताह किया गया। 6-8 सप्ताह के बीच वैक्सीन का डोज लेने से प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ती है।
- भले ही आपके दूसरे डोज के लिए तिथि ऑटो शेड्यूल हो गई हो, आप विस्तारित अवधि के बीच एक निश्चित दिन और तारीख चुन सकते हैं। अपने अपॉइंटमेंट को फिर से निर्धारित करने के लिए www.cowin.gov.in पर विजिट करें।
- 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण करा सकते हैं, इसके लिए अब किसी गंभीर बीमारी का होना आवश्यक नहीं है।
- 1 जनवरी 1977 से पहले जन्म लेने वाले सभी लोग टीकाकरण के लिए पात्र हैं।
- कोविन सिस्टम पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2021 से चालू हो गई है। इस तारीख से ऑनलाइन के साथ-साथ ऑनसाइट पंजीकरण शुरू हो चुका है।
- कोविन एप पर टीकाकरण के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाले लाभार्थियों को निजी या सार्वजनिक अस्पतालों में फिर से अपॉइंटमेंट लेने की जरुरत नहीं होगी।
- यदि कोई अस्पताल टीकाकरण प्रमाण पत्र के प्रावधान सहित नए टीकाकरण दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो आप टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
- देश में टीकों की कोई कमी नहीं है। लोगों को अनावश्यक रूप से नहीं घबराना चाहिए।

सावधानी अब भी जरूरी, क्योंकि फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े

कोरोना के मामले फिर एक बार बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम सतर्कता बरतें। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। 4 अप्रैल को पूरे देश में 1,03,794 नए मरीज मिले। इनमें से 54,074 केस अकेले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहां सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।

5 अप्रैल तक के आंकड़ों के अनुसार करीब 7,91,05,163 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है।

वैक्सीन मैत्री...29 मार्च तक भारत दुनिया के 84 देशों को कोरोना वैक्सीन के 6 करोड़ 45 लाख 26 हजार डोज भेज चुका है। इनमें से 1करोड़ 5 लाख डोज बतौर उपहार दिए गए हैं।

वक्त से पहले पूरा हुआ हेल्थ-वेलनेस सेंटर का लक्ष्य

पहली बार स्वास्थ्य किसी सरकार के एजेंडे का प्रमुख आधार स्तंभ बना है। इसी का नतीजा है कि 31 मार्च 2021 तक 70 हजार हेल्थ-वेलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य 10 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया है। यानी 21 मार्च तक देश में 70,015 आयुष्मान भारत- हेल्थ वेलनेस सेंटर चालू हो गए हैं। इनका लाभ 41.35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है।

डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में देश की ई-संजीवनी

कोरोना काल से चंद महीने पहले शुरू हुई टेलिमेडिसिन सेवा- ई-संजीवनी ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 30 लाख ज्यादा परामर्श दिए हैं। यह सेवा 31 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है और रोजाना देश के 35 हजार से अधिक मरीज ई-संजीवनी का उपयोग कर रहे हैं। ई-संजीवनी ओपीडी के तहत 21 लाख से अधिक रोगियों को सेवा दी गई ।

नतीजा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से प्री-मैच्योर मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिस पर संयुक्त राष्ट्र के प्रशिक्षण और अनुसंधान (UNITAR) ने भी भारत की प्रशंसा की है क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के मामलों में भारत दुनिया में सबसे आगे है। ●

डाक बैंक | आपका बैंक आपके द्वार

जीएसटी, आधार और जनधन खातों के साथ देश की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप देने के क्रम में 1 सितंबर 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपना खाता खोलकर इंडिया पोस्ट बैंक की शुरुआत की थी। मकसद था, देश के सुदूर इलाके तक मौजूद सवा लाख डाकघरों और 3 लाख डाकियों के विशाल नेटवर्क का उपयोग आम आदमी के हित में किया जा सके और उन्हें बैंकिंग सेवाएं उनके द्वार पर मिले...

तमिलनाडु के मुगैयूउर (थोपू) गांव में रहने वाले बुजुर्ग सुंदरम शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं। उनके सबसे नजदीक सरकारी बैंक की शाखा 10 किमी दूर है। दिव्यांग और बुजुर्ग होने के कारण रुपया निकालने के लिए बैंक जाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उन्हें परेशान देख कर पोस्टमास्टर अरूण सेल्वा कुमार ने उन्हें डाक घर से चलने वाली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) सेवा के बारे में बताया। सुंदरम को न तो अब खाते से रुपया निकालने के लिए 10 किमी दूर जाना होता है और न पर्ची भरवाने के लिए बैंक कर्मचारियों की मिन्नतें करनी पड़ती है। अब वह केवल डाकिया के पास उपलब्ध बायोमीट्रिक उपकरण पर अंगूठा लगाकर आसानी से रुपया निकाल लेते हैं। आज अगर देश के करोड़ों लोग केवल अंगूठा लगाकर आसानी से रुपया निकाल पाने में सक्षम हो पा रहे हैं तो उसकी वजह है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। संचार मंत्रालय के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रांची और रायपुर से शुरु होने वाली यह सेवा अब देश के हर जिले में मिल रही है।

अब आपके घर आया बैंक

खाता खोलना हो या अपने खाते में किसी सुविधा का लाभ उठाना हो, अब सिर्फ एक मैसेज भेज कर आप डाकिए को अपने घर बुलाकर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) आम आदमी के लिए एक सुलभ, सस्ता और विश्वसनीय बैंक है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए 1 लाख 36 हजार 78 एक्सेस पॉइंट की शुरुआत की गई है। बैंकिंग सेवाओं के लिए 25 हजार 259 काउंटर बनाए गए हैं। यही नहीं, देशभर में 2.90 लाख डाकिए यह सारी बैंकिंग सेवाएं मोबाइल फोन और बायोमीट्रिक उपकरण लेकर अब आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए मौजूद हैं।

कोरोना महामारी के दौरान डाक बैंकिंग की भूमिका...

- **लॉकडाउन और अनलॉक के पहले चरण के दौरान कोर बैंकिंग सेवा (सीबीएस) - पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (पीओएसबी) खातों में काउंटर ऑपरेशन के जरिए 48.82 करोड़ बार में करीब 9.86 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ।**
- **पीओएसबी एटीएम के जरिए करीब 1.06 करोड़ बार में 3,551 करोड़ रुपये निकासी की गई।**
- **कोरोना से पहले और 1 सितंबर 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 के बीच आईपीपीबी ने 25.7 लाख से अधिक एईपीएस से 848 करोड़ रुपया वितरित किया।**

दो सेवाएं जिनकी शुरुआत पहली बार हुई...

- डाकियों और ग्रामीण डाक घरों के जरिए हर घर के दरवाजे तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से देश भर के गरीबों और दूरदराज पहाड़-जंगलों में बसे लोगों के दरवाजे तक बैंक पहुंचाने का संकल्प पूरा होने का रास्ता खुल गया है। अब हम बैंक को गांव और गरीब के दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। 'आपका बैंक आपके द्वार' यह हमारा कमिटमेंट है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

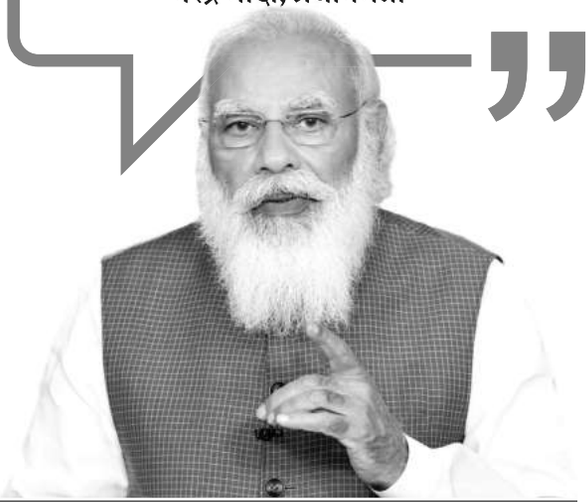

- ऐसी सहायक सेवाएं मुहैया कराना जो उन लोगों की मदद करे जिन्हें नकदी से डिजिटल बैंकिंग में बदलाव के बारे में कोई अनुभव नहीं है।

ऐसे हुई डाक बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत

साल था 1833, जब कलकत्ता (अब कोलकाता) में देश का पहला सरकारी बचत बैंक खोला गया था। इसके बाद, डिस्ट्रिक बैंक, प्रेसीडेंसी बैंक, रेलवे बैंक और रेजिमेंटल बैंक जैसे और कई सरकारी बैंक खोले गए। बाद में, साल 1873 में बचत बैंक अधिनियम लागू किया गया जिससे इस योजना का एक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार हो गया। पोस्ट ऑफिस बचत बैंक ने एक अप्रैल 1882 से काम करना शुरु किया और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से उपरोक्त सभी बैंकों का पोस्ट ऑफिस बचत बैंक में विलय हो गया। 1947 में आजादी के बाद तत्कालीन भारत सरकार को लगा कि बचत गतिविधि को और तेज करना चाहिए और इसके बाद 1948 में राष्ट्रीय बचत संगठन एनएसओ (अब एनएसआई) का गठन किया गया। भारत में यह डाक घर बैंकिंग की शुरुआत थी तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डाक घर बैंकिंग के स्तर को सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है।

आप ऐसे ले सकते हैं लाभ...

इंडिया पोस्ट पेमेंट के मोबाइल एप के जरिए भी आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नजदीकी डाकघर में जाकर भी खाता खुलवाया जा सकता है।

आपकी बचत, आपकी सुरक्षा

- **डाक घर बचत खाता (एसबी) :** केवल 500 रुपये से शुरुआत कर आप डाक घर में बचत खाता खोल सकते हैं।
- **5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता (आरडी) :** छोटी बचत का बड़ा सहारा। 5 साल के मेच्योरिटी पीरियड के लिए न्यूतम 100 रुपये प्रतिमाह पर डाक घर आरडी की सुविधा देता है।
- **डाकघर सावधि जमा खाता(टीडी) :** डाक घर में टाइम डिपॉजिट अकाउंट कम से कम 1000 रुपये से खोला जा सकता है। इस स्कीम में 5 साल के लिए किए गए निवेश पर टैक्स छूट 80C के तहत ली जा सकती है।
- **राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता (एमआईएस) :** 1000 के गुणक में प्रतिमाह रुपये जमा किए जा सकते हैं। इस पर 6.6% की दर से ब्याज मिलता है।
- **वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता :** 60 से ऊपर कोई भी व्यक्ति या 55 से 60 साल के बीच रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी खाता खोल सकता है। इस पर 7.4% ब्याज मिलता है।
- **पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट :** एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 और अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। इस पर 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
- **सुकन्या समृद्धि खाता :** वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 और अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
- **राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र :** इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। परिपक्वता अवधि 5 साल है।
- **किसान विकास पत्र :** कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 1000 रुपये निवेश कर सकता है। 124 महीने के बाद आपको 6.9% की दर से निवेश की राशि दोगुनी करके दी जाएगी।
- **वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सर्विस:** ऑनलाइन राशि भेजने या मंगाने की सुविधा।
- इसके अतिरिक्त डाकघर में लंबी अवधि की निवेश योजना यूटीआई के साथ नेशनल पेंशन स्कीम और दुर्घटना बीमा योजना जन सुरक्षा का लाभ भी उठाया जा सकता है। ●

सुविधाओं के राजमार्ग

राजमार्ग निर्माण की गति हो या उसके किनारे यात्रियों-ट्रक ड्राइवरों के अनुकूल सुविधाओं का विकास या इंफ्रास्ट्राक्चर को नया स्वरुप देना या फिर पर्यटक वाहनों के लिए एक देश-एक व्यवस्था की पहल, केंद्र सरकार विकास की प्रतिबद्धता को अब नए-नए आयाम दे रही है ताकि जन-जीवन को मिले सहुलियत और पैदा हो रोजगार के नए अवसर

राजमार्ग पर अक्सर सफर करने वाली इंदु कहती हैं, "थोड़ी-थोड़ी दूरी पर एक टॉयलेट का होना जरूरी है।" जबकि ऐसे ही यात्री यदुवीर सिंह ठहरने की व्यवस्था, तो हुसैन अब्बास रास्ते में होटल और खाने-पीने की साफ-सुथरी व्यवस्था चाहते हैं। सड़क मार्ग पर अपने या पर्यटक वाहन से यात्रा करने वाले इन यात्रियों से अलग ट्रक ड्राइवर हरि राम कहते हैं कि ट्रकों में माल ढोते वक्त उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य जाते वक्त कई रात सफर में गुजारना पड़ता है। ऐसे में वे चाहते हैं, "हाई-वेज किनारे खाने-पीने, नहाने-धोने, गाड़ी रखने और 4-5 घंटे सुकून से रहने की व्यवस्था होनी चाहिए।" एक अन्य ट्रक ड्राइवर जीतेंद्र चौहान इसमें जोड़ते हैं कि हर 40-60 किमी की दूरी पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए तो अच्छा रहेगा।

अब इंदु, यदुवीर जैसे यात्रियों और हरि राम, जीतेंद्र जैसे ट्रक ड्राइवरों का सपना साकार होने जा रहा है क्योंकि एनएचएआई की अगली पहल में व्यक्तिगत वाहन चालकों, ट्रक चालकों और सहायक चालकों के लिए विश्व स्तर की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके लिए नए विश्व स्तरीय दिशा निर्देशों के तहत योजना बनाई गई है। जिसके मुताबिक हर 40 से 60 किमी के अंतर पर राजमार्गों के किनारे जन सुविधा को विकसित करने का प्रावधान है। एनएचएआई सभी प्रमुख ट्रकिंग कॉरीडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वेज को कवर करते हुए सड़क किनारे की जन सुविधाओं का एक राष्ट्रव्यापी ग्रिड विकसित कर रहा है। इन सुविधाओं में पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट, रेस्त्रां, ढाबा, दुकानें, मेडिकल सुविधाएं, स्थानीय हाट-बाजार और स्वच्छ शौचालय शामिल हैं। अगले पांच वर्षों में 600

3 गुना रफ्तार से राजमार्ग का हो रहा निर्माण

अब प्रतिदिन 34 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। जबकि 2014 में यह दर महज 12 किमी प्रतिदिन थी। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2020-21 में 12,205 से अधिक किमी राजमार्ग का निर्माण करके देश ने एक और मील का पत्थर पार किया है। जबकि उस साल के लिए लक्ष्य महज 11 हजार किमी का था, जिससे 1205 किमी अतिरिक्त सड़कें समय से पहले (22 मार्च तक) बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है।

18 घंटे में 25 किमी राजमार्ग, लिम्का बुक में दर्ज

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के देश भर में चल रहे कार्यों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में देश ने अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। ये कीर्तिमान फोर लेन सोलापुर-बीजापुर के करीब एक लेन में 25.5 किमी राजमार्ग का निर्माण 18 घंटे में पूरा करके स्थापित किया गया है। एनएचएआई की उस उपलब्धि को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 110 किमी लंबे इस राजमार्ग का उद्घाटन पिछले साल ही हुआ था।

यात्रा और पर्यटन को प्रोत्साहन

किसी राज्य की सीमा में प्रवेश पर पर्यटक वाहन को शुल्क अदा करने में देरी होती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार की एक देश, एक व्यवस्था की दिशा में बड़ी पहल हुई है। इसके लिए अखिल भारतीय पर्यटक वाहन परमिट रूल 1 अप्रैल से लागू हुआ। इसके तहत पर्यटक वाहन संचालक अब ऑनलाइन मोड के माध्यम से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक बार में तीन साल तक के लिए भी अनुमति दी जा सकती है।

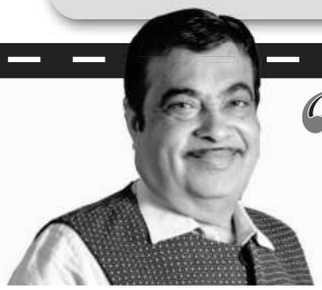

एनएचएआई अगले पांच साल में देश के 600 से ज्यादा जगहों पर राजमार्गों के किनारे यात्रियों से जुड़ी जन सुविधा को विकसित करने जा रहा है, जो लाखों लोगों के लिए एक नया अवसर पैदा करेगा और यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के साथ-साथ ट्रक ड्राइवरों के जीवन को सुधारेगा। - नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री

से ज्यादा जगहों पर इस तरह की सुविधाएं विकसित की जानी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) देश के एक सबसे बड़े बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम 'भारतमाला परियोजना' का संचालन कर रहा है, जिसके तहत देश में कई हाईवेज और एक्सप्रेस-वेज विकसित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार इन सुविधाओं का भी विकास 5,35,500 करोड़ रुपये की लागत वाली भारतमाला परियोजना के तहत ही कर रही है।

चारों दिशा में सुविधाओं का होगा विकास: इस तरह की सुविधाओं का विकास 3 हजार से ज्यादा हेक्टेयर में किया जाना है। इसमें उत्तर में 67, पूर्व में 40, पश्चिम में 29, दक्षिण में 45, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 94, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज-हाईवेज पर 376 जगह चिन्हित की गई हैं।

ट्रक ड्राइवरों के लिए डॉरमेट्री: ट्रक ड्राइवरों के लिए अपने ट्रक पर लदे माल की चिंता किए बिना आराम करने की सुविधा उनकी यात्रा को और सुखद बनाएगी क्योंकि इसके लिए डॉरमेट्री भी बनेगी। कुछ बड़ी जगहों पर इमरजेंसी के लिए हेलीपैड की भी सुविधा होगी।

स्थानीय कला को मिलेगा बढ़ावा: हाट-बाजारों के विकास से स्थानीय व्यवसायियों को अपनी स्थानीय कला-कृतियों का प्रदर्शन और बिक्री करने का अवसर मिलेगा। जिससे पूरे हस्तकला और कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

व्यवसायियों को रियायतें: परियोजना में शामिल होने की योग्यता के मानदंड में ढाबे और रेस्त्रां, फ्यूल स्टेशन मालिकों, होटल और मोटेल ऑपरेटरों आदि के साथ ही विभिन्न व्यवसायियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अब पर्याप्त रियायतें भी दी गई हैं।

आरामदायक सफर में ऐसी आवश्यक सुविधाओं में कमी न सिर्फ यात्रा के आनंद को कम करती है, बल्कि विकास की रफ्तार को भी तेजी देती हैं। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण साबित होगी। ●

चिरंजीवी

भारत-बांग्लादेश मैत्री

साझी ऐतिहासिक विरासत, भाषायी-सांस्कृतिक रिश्ते, संगीत, साहित्य और कला के लिए लगाव, भारत-बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों का अहम आधार है। अब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर्रहमान के जन्म शताब्दी वर्ष, बांग्लादेश की आजादी और भारत के साथ उसके संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 26-27 मार्च को ढाका यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नए युग की हुई शुरुआत, जहां पीएम ने दिया संदेश- "भारोत बांग्लादेश मोईत्री चिरोजीबि होख।"

एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में दिसंबर 1971 में दुनिया के मानचित्र पर उभरने वाले बांग्लादेश को मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। बांग्लादेश के विकास में भारत हर तरह से मददगार पड़ोसी की भूमिका निभाता रहा है। लेकिन कोरोना काल के बाद से जिस तेजी से क्षेत्रीय और वैश्विक राजनैतिक परिदृश्य बदल रहे हैं उससे दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ रिश्तों की जरूरत अब कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। ऐसे में जब पड़ोसी राष्ट्र अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ और अपने जनक का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है, 'पड़ोसी पहले की नीति' पर कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में साल भर बाद विदेश यात्रा की शुरुआत बांग्लादेश से कर रिश्तों को नया आयाम देने की पहल की है। 26-27 मार्च को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने मेल खाती सभ्यता-संस्कृति वाले बांग्लादेश के साथ सामाजिक-आर्थिक संपर्कों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री ने बंगबंधु के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस को संबोधित किया तो ओराकंदी में ठाकुरबाड़ी मंदिर में पूजा की और मतुआ संप्रदाय को भी संबोधित किया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय

संबंधों को लेकर संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया, जिसमें बांग्लादेश ने भारत के निरंतर सहयोग के लिए आभार जताया तो भारत की ओर से भी बांग्लादेश के विकास की सराहना की। क्षेत्र और दुनिया में भागीदारी को मजबूत करने के लिए एक-दूसरे के सहयोग के लिए भी दोनों देशों ने धन्यवाद दिया और द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और आदान-प्रदान किया गया। भारत ने बांग्लादेश को भरोसा दिया कि वह अपने पड़ोसी के विकास में मजबूत सह-भागीदार बना रहेगा।

इस यात्रा की महत्ता को बांग्लादेश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के संदेश से भी समझा जा सकता है, "मुझे खुशी है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद किसी ऐसे पड़ोसी मित्र देश की यह मेरी पहली विदेश यात्रा है, जिसके साथ भारत के सांस्कृतिक, भाषाई और दोनों देशों के लोगों के बीच आपस में गहरे संबंध हैं।" इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेशी अखबार 'द डेली स्टार' में "बंगबंधु के साथ एक अलग दक्षिण एशिया की कल्पना" शीर्षक से एक लेख भी लिखा। जिसमें प्रधानमंत्री ने वादा किया कि भारत हमेशा बांग्लादेश का साझीदार रहेगा क्योंकि दोनों देश स्वर्णिम भविष्य की ओर मिलकर बढ़ रहे हैं, जिसके लिए बंगबंधु, लाखों देशभक्त बांग्लादेशी और निश्चित तौर पर हजारों भारतीयों ने पूरी कोशिश की है।

साझी विरासत और आम चुनौतियां

बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह के जश्न के लिए ढाका में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-बांग्लादेश संबंधों, दोनों देशों की साझी विरासतों और साझा लक्ष्यों पर विस्तार से बात की। दोनों देशों के मजबूत संबंधों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विरासत भी साझा हैं, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं और हमारी चुनौतियां भी साझा हैं। पीएम मोदी ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारतीय सेना के योगदान की भी सराहना की। इस दौरान पीएम ने अपने जीवन के उस पल को भी साझा किया कि कैसे उन्होंने भी बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था।"

बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह पर ढाका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि जहां व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में दोनों देशों के पास एक समान अवसर हैं वहीं उनके सामने आतंकवाद जैसी एक समान चुनौतियां भी हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बांग्लादेश के 50 उद्यमियों को भारत आकर यहां के स्टार्ट अप और इनोवेशन के तंत्र से संपर्क स्थापित करने और उद्यमियों से मिलने का न्यौता भी दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 50 साल पूरा होने के अवसर पर बांग्लादेशी छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की भी घोषणा की। इस समारोह में बंगबंधु को श्रद्धांजलि देने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर से खादी का बना काले रंग का 'मुजीब जैकेट' भी पहना। बांग्लादेश में बेहद लोकप्रिय मुजीब जैकेट, ऊंचे गले का बिना बांह का पुरुषों का पहने जाने वाला कोट है। भारत के खादी ग्रामोद्योग ने खास तौर से 100 मुजीब जैकेट इस समारोह के लिए तैयार करके ढाका भेजे थे।

बांग्लादेशी नागरिकों के सेहत की भी फिक्र

इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने राजनैतिक और सामुदायिक नेताओं से भी मुलाकात की, जिनमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के मुक्ति योद्धा शामिल रहे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम

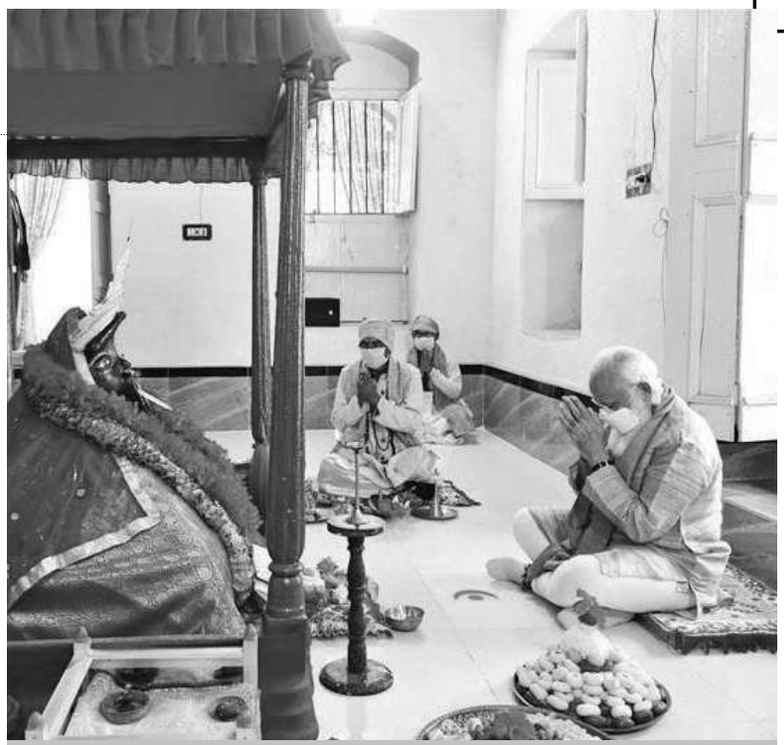

जेशोरेश्वरी मंदिर में की पूजा-अर्चना

प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा से पहले बांग्लादेश के सतखीरा स्थित जेशोरेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर को बड़े खूबसूरत ढंग से सजाया गया। यह मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में प्रधानमंत्री ने मां काली की पूजा-अर्चना भी की। प्रधानमंत्री ने ओराकान्दी में मतुआ समुदाय के प्रतिनिधियों को भी संबोधित किया। ये वही स्थान है, जहाँ से श्री श्री हरि चंद ठाकुर जी ने सामाजिक सुधारों से संबंधित अपने पवित्र विचारों और संदेशों का प्रसार किया था।

भरोसे की डगर, प्रगाढ़ होते रिश्ते

रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग

2020 में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सहयोग। भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सेना को प्रशिक्षित घोड़े और कुत्ते उपहार में दिए। बांग्लादेश विजय दिवस के मौके पर मुक्तियोद्धा के परिजनों को स्कॉलरशिप के साथ उनके लिए स्वास्थ्य योजना शुरू की गई।

सुरक्षा और सीमा प्रबंधन

- भारत-बांग्लादेश के बीच 4096.7 किमी की सबसे बड़ी भूमि सीमा है, जिसे भारत अपने किसी पड़ोसी देश के साथ साझा करता है, इसमें 1116.2 किमी सीमा नदी तट से संबंधित है।
- शीर्ष स्तर पर बांग्लादेश के नेतृत्व ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा।
- जून 2015 में पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के वक्त लिखित पुष्टि के बाद दोनों देशों के बीच बांग्लादेश भूमि सीमा करार लागू हुआ।
- 7 जुलाई 2014 को अंकलोस पांचाट के अनुसार दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा मध्यस्थता ने बंगाल की खाड़ी के इस भाग के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जो दोनों देशों के लिए लाभकारी है।
- दोनों देशों के बीच 54 नदियां समान रूप से बहती हैं। इनसे अधिकतम लाभ और संपर्क स्थापित करने के लिए जून 1972 से द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग काम कर रहा है। हस्ताक्षरित गंगा जल संधि आज भी संतोषप्रद ढंग से काम कर रही है।

कनेक्टिविटी

- 17 दिसंबर 2020 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने बांग्लादेश के चिल्हाटी से हल्दीबाड़ी (भारत) के बीच रेल लिंक का उद्घाटन किया।
- दो पैसेंजर ट्रेन- मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाए गए हैं।
- अक्टूबर 2019 में ढाका-सिलिगुड़ी-गंगटोक-ढाका और ढाका-सिलिगुड़ी-दार्जिलिंग-ढाका बस सेवा शुरू हुई।
- त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने वाले मैत्री सेतु की शुरुआत 9 मार्च 2021 को की गई।

आर्थिक-वाणिज्यिक

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- बीते कुछ वर्षों में भारत से बांग्लादेश को निर्यात तीन गुना हो गया है। वर्ष 2019-20 में 8.2 बिलियन डॉलर का निर्यात बंग्लादेश को किया गया और 1.26 बिलियन डॉलर का आयात हुआ।
- बिजली क्षेत्र दोनों के बीच सहयोग की बड़ी पहचान है। बांग्लादेश 1160 मेगावाट बिजली भारत से आयात कर रहा है।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

2019 से अब तक बांग्लादेश के 1800 प्रशासनिक अधिकारियों को मसूरी स्थित नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में प्रशिक्षण दिया गया।

बांग्लादेश के पुलिस अधिकारियों के साथ 2017 से अब तक 1500 न्यायिक सेवा के अधिकारियों को भी भारत में प्रशिक्षण दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी छात्रों को हर साल 200 स्कॉलरशिप दी जाती है।

मोदी ने सत्तारूढ़ ग्रैंड अलायंस के नेताओं से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस यात्रा में बोहरा समुदाय के नेताओं ने ढाका में पीएम मोदी से मुलाकात कर कोरोना वैक्सीन के लिए धन्यवाद दिया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंजुमन-ए-जमात के सचिव कय्यूम दीसावाला ने किया। बैठक के बाद कय्यूम दीसावाला ने कहा कि पीएम मोदी ने बोहरा समुदाय के लोगों से गुजराती भाषा में बात की। दोस्ती के साथ 12 लाख कोरोना वैक्सीन की नई खेप लेकर खुद पीएम मोदी बांग्लादेश पहुंचे थे, जिसमें सिर्फ दोस्ती और साझेदारी का पैगाम नहीं, बल्कि आम बांग्लादेशी नागरिकों की सेहत की फिक्र का भी संदेश था।

सहयोग और संवाद से संबंधों को मजबूती

कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति के बावजूद बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों में आत्मीयता बनी रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नए साल पर एक-दूसरे को बधाई दी। जबकि इससे पहले 17 मार्च 2020 को शेख मुजीबीर्रहमान के जन्म शताब्दी

बांग्लादेश में भारतीय समुदाय

एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के 10 हजार लोग रहते हैं, जिनकी मेहनत और प्रबंधकीय कौशल ने पड़ोसी देश में उन्हें सम्मान दिलाया है। अधिकांश भारतीय समुदाय रेडीमेड गारमेंट के व्यवसाय से जुड़े हैं या मल्टी नेशनल कंपनियों में शीर्ष जगहों पर हैं। भारतीय समुदाय वहां समय-समय पर इंडियन एसोसिएशन और ढाका एसोसिएशन के साथ मिलकर सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करता रहता है।

वर्ष के लिए पीएम मोदी ने वीडियो संदेश दिया और 29 अप्रैल को रमजान की और 25 मई को ईद की शुभकामनाएं दी। 17 दिसंबर 2020 को दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान हाइड्रोकार्बन, कृषि, व्यापार, विकास की परियोजनाएं और विरासत के संरक्षण पर समझौते हुए। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान पर भारत सरकार की ओर से समर्पित स्मारक डाक टिकट जारी किया। राजशाही शहर और खुलना में खालिसपुर कॉलेजिएट छात्रा स्कूल का उद्घाटन किया गया। 29 सितंबर 2020 को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर बांग्लादेश सरकार की ओर से जारी डाक टिकट को समर्पित किया। 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर से बांग्लादेश के राष्ट्रपति मो. अब्दुल हामिद शामिल हुए थे। इससे पहले 3-6 अक्टूबर 2019 को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आधिकारिक दौरे पर भारत आईं। 22 नवंबर 2019 को उन्होंने कोलकाता का भी दौरा किया जहां भारत-बांग्लादेश के बीच हुए पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट मैच की साक्षी बनीं। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बैठक के दौरान सितंबर 2019 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया था। बहुआयामी और विभिन्न विषयों पर दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत होती है, जिनमें पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अणु विज्ञान और आईटी शामिल है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए खास तौर से 19 अगस्त 2015 को नई दिल्ली का दौरा किया था। ●

बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

बंगबंधु और बिन अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार

बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीबुर्रहमान के जन्म शताब्दी वर्ष पर भारत ने 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा तो 2019 का यह पुरस्कार ओमान के (दिवंगत) महामहिम सुल्तानकाबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया

'मुजीब वर्ष' में बंगबंधु के संघर्ष को सम्मान

कहा जाता है कि अगर शेख मुजीबुर्रहमान नहीं होते तो बांग्लादेश का उदय भी नहीं होता। गांधीवादी रास्ते पर चलकर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की जो दिशा उन्होंने दी, उसके लिए ही बांग्लादेश की आवाम ने उन्हें 'बंगबंधु' की उपाधि दी है। ऐसे में जब बांग्लादेश 'मुजीब वर्ष' मना रहा है भारत भी बांग्लादेश सरकार और उसके लोगों के साथ मिलकर उनकी विरासत को याद करते हुए शेख मुजीबुर्रहमान को गांधी शांति पुरस्कार दिया। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे 1995 से प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी।

भारत-ओमान संबंधों के शिल्पकार काबूस

महामहिम सुल्तान काबूस एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में संयम और मध्यस्थता की जुड़वां नीति ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा और सम्मान दिलाया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय विवादों और संघर्षों में शांति प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम सुल्तान काबूस भारत और ओमान के बीच विशेष संबंधों के शिल्पकार थे। उन्होंने भारत में पढ़ाई की थी और हमेशा भारत के साथ एक विशेष संबंध बनाए रखा। उनके नेतृत्व में, भारत और ओमान रणनीतिक भागीदार बने।

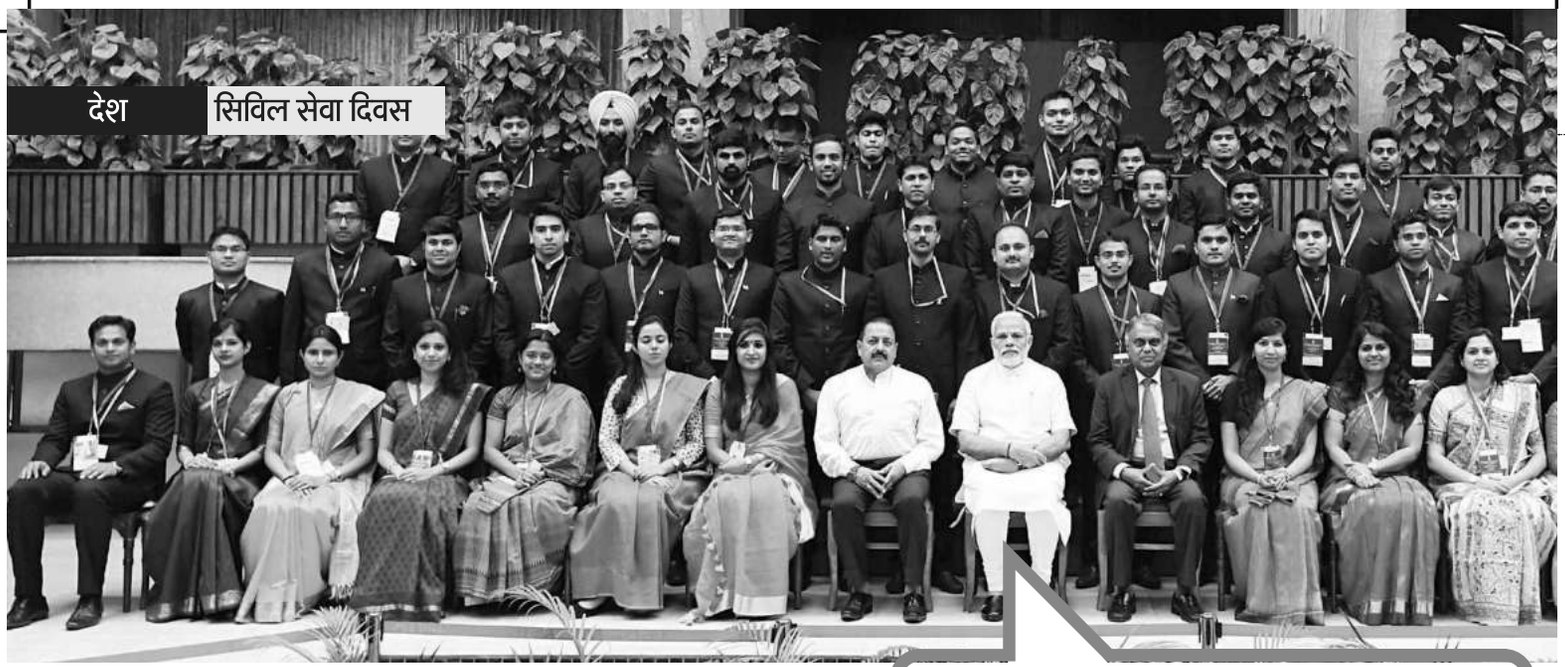

सदैव देश की सेवा में...

> *आप केवल करियर या महज नौकरी के लिए इस पथ पर नहीं आए हैं। आप सेवा परमो धर्म के मंत्र के साथ यहां सेवा के लिए आए हैं। आपका एक कदम, एक हस्ताक्षर लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा। आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि आपका निर्णय राष्ट्र को किस तरह प्रभावित करेगा।*
>
> **नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री** (31 अक्टूबर 2020)

21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें 'स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया' कहा था। क्योंकि सरकार की नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन में सबसे अहम भूमिका इन्हीं की होती है...

प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होनी वाली फसलों पर उचित मुआवजे के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। लेकिन इस योजना को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी थी जिला प्रशासन की और त्रिपुरा के पश्चिमी त्रिपुरा जिले के प्रशासन ने इस मामले में उम्मीद से बढ़कर काम किया। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार कर हर एक किसान तक इस योजना की सही जानकारी पहुंचाई गई, ताकि वह इसका लाभ सही तरीके ले सकें। इसी तरह हरियाणा के सोनीपत का उदाहरण भी अनुकरणीय है। जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए सक्षम युवा कार्यक्रम का नतीजा है कि यहां पहले बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान केवल 4% लोग करते थे, अब उनकी संख्या 88% पहुंच गई है। डिजिटल भुगतान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन के 10 लाख से ज्यादा एसएमएस भेजे, वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार किया गया। इन अनुकरणीय उदाहरणों के लिए दोनों को ही वर्ष 2018 में 'प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' भी दिया गया है।

आने वाले 25 सालों में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान क्या होगा, इसका दायित्व हमारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर ही है।

दरअसल, सरकार आम जन के हित में जो योजनाएं बनाती है, उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की ही होती है। सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, "ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम, ये दो ऐसे शब्द बन गए हैं जिनको बुरी ब्यूरोक्रेसी या बुरा सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती।"

इसी छवि को तोड़ने की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई है। इसी के चलते केंद्रीय योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सफलता मिली है। सिविल सर्विस दिवस के अवसर पर जन सेवा की भावना से काम

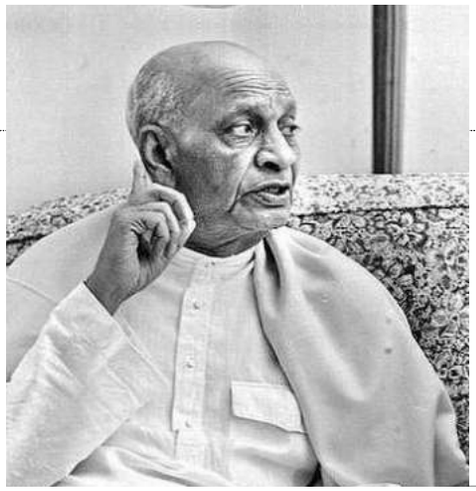

लोकसेवा सरकार का सबसे प्रत्यक्ष 'चेहरा' है, क्योंकि तमाम सेवाओं के लिए नागरिकों का पाला उन्हीं से पड़ता है। सरकार की छवि भी काफी हद तक लोकसेवकों के इसी रवैये पर निर्भर करती है कि वे लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे करते हैं।

– सरदार वल्लभ भाई पटेल

सिविल सेवा का इतिहास... सिविल सेवा शब्द ब्रिटिश काल में आया था और इस सेवा में काम करने वालों को 'लोक सेवक' के रूप में जाना जाता था। इसकी नींव वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी थी। बाद में चार्ल्स कॉर्नवॉलिस ने इसमें और अधिक सुधार किए गए। प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाली ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजी राज से मुक्त हुई और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन सिविल सर्विस से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का गठन किया।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य

- सिविल सेवा अधिकारियों के कार्य और प्रयासों को प्रेरित करना और उनकी सराहना करना। केंद्र सरकार इस अवसर का उपयोग सिविल सेवाओं के तहत विभिन्न विभागों के काम का मूल्यांकन करने के लिए करती है।
- केंद्र सरकार सबसे अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों और समूहों को पुरस्कार देती है। इस दिन ज्यादातर केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में उनकी असाधारण सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाता है।
- **सरकार ने भूमिका आधारित एप्रोच पर बहुत जोर दिया है। इसके नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं।** सिविल सर्विसेस में क्षमता और सामर्थ्य निर्माण के लिए नया आर्किटेक्चर खड़ा हुआ है। सीखने के तौर-तरीके का लोकतंत्रीकरण हुआ है। हर ऑफिसर के लिए उसकी क्षमता और अपेक्षा के हिसाब से उसका दायित्व भी तय हो रहा है।

ऐसे हुआ पुरस्कार में बदलाव

अब प्रमुख कार्यक्रमों और इनोवेशन की कैटेगिरी में भी पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। प्रमुख कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, नमामि गंगे योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और डिजिटल भुगतान जैसे प्राथमिकता वाले प्रमुख कार्यक्रमों के लिए पुरस्कार भी दिए गए हैं। ये प्राथमिकता वाले कार्यक्रम नए भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। जिन योजनाओं के लिए सम्मान दिया जा रहा है, ये न्यू इंडिया के हमारे जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

करने वालों को इसके लिए 'प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' पुरस्कार भी दिया जाता है। वैसे तो सिविल सेवा दिवस कई सालों से मनाया जा रहा है लेकिन 2014 के बाद से इसके स्वरूप में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब यह एकेडमिक कैलेंडर ऑफ इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण दिवस बन गया है। इसमें अलग-अलग सत्र में अलग-अलग विषयों पर चर्चा आयोजित की जाती हैं। इसी तरह पुरस्कारों की श्रेणी में भी बदलाव किए गए हैं। पहले किसी अधिकारी को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार दिए जाते थे लेकिन अब सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के आधार पर भी पुरस्कार दिए जाने लगे हैं। यही कारण है कि साल 2016 में जहां 74 जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे वहीं 2017 में 599 जिलों ने इसमें भाग लिया और साल 2018 में यह संख्या बढ़ कर 643 हो गई। 2017 में 599 जिलों से 2345 प्रस्ताव आए थे जबकि 2018 में 643 जिलों से 3009 प्रस्ताव आए। इनमें से 999 यानि एक तिहाई प्रस्ताव केवल इनोवेशन कैटोगरी में आए थे। साल 2020 में देश के कुल 736 जिलों में से 702 जिलों ने इसमें हिस्सा लिया। ●

सकारात्मक कहानी

जिंदगी और पर्यावरण बचाने की अनोखी पहल

जीवन के साथ-साथ पर्यावरण का अपना एक अलग महत्व है। ऐसे में इसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है और इसे बचाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिंदगी बचाने के इसी काम में लगे हैं राघवेंद्र, जो लोगों को हेलमेट बांट कर दुर्घटना से बचा रहे हैं। वही, एन. एस. राजप्पन झील से कचरा निकाल कर जुटे हैं पर्यावरण बचाने के काम पर...

किताब के बदले हेलमेट देकर बचा रहे लोगों की जिंदगी

एक सड़क दुर्घटना में अपने मित्र को खोने के बाद राघवेंद्र हादसे से लोगों की जान बचाने के लिए वाराणसी में लोगों को हेलमेट देने के काम में जुटे हुए हैं। उनके इस काम के कारण अब लोग उन्हें हेलमेट मैन के नाम से पुकारते हैं और लोगों के बीच उनकी चर्चा होने लगी है। लोगों को हेलमेट देने के बदले में राघवेंद्र किताब लेते हैं। इतना ही नहीं वो लोगों को हेलमेट देकर शपथ भी दिलाते हैं कि बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाएंगे और दूसरों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करेंगे। दरअसल, एक सड़क दुर्घटना में राघवेंद्र के दोस्त की मौत हो गई थी और उसने हेलमेट नहीं लगाया था। इस घटना ने राघवेंद्र को इस कदर झकझोर दिया कि उन्होंने तय किया कि वो लोगों को इसे लेकर जागरूक बनाएंगे। ऐसे में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और लोगों को मुफ्त में हेलमेट बांटने का अभियान शुरू कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर साल सड़क दुर्घटना में डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है। जिनमें 50 हजार लोग ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ●

झील से कचरा निकाल पर्यावरण बचा, संवार रहे हैं लोगों की जिंदगी

केरल में कोट्टयम के निवासी एन. एस. राजप्पन दिव्यांग हैं और चलने में असमर्थ हैं। बावजूद इसके, वह पिछले छह सालों से हर रोज नाव में बैठकर वेम्बनाड झील में जाते हैं और वहां से प्लास्टिक का कचरा निकालकर बाहर फेंकते हैं। राजप्पन के घुटने से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड है, जिसके कारण वे चल नहीं पाते। बावजूद इसके वे अपने हाथ के सहारे आगे बढ़ते हैं और झील से कचरा बाहर निकालते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एन.एस.राजप्पन के काम और स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की थी। दरअसल, वेम्बनाड झील की सुंदरता दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। राजप्पन की अथक मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि झील आज स्वच्छता की बानगी कहती है। अपने काम के कारण एन. एस राजप्पन आज अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। ●

67 वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-2019

67 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 3 मई 2020 को ही होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। 22 मार्च 2021 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की ज्यूरी ने 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों घोषणा की...

कंगना रनौत

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मणिकर्णिका-द क्वीन ऑफ झांसी और फिल्म पंगा

कंगना ने जहां मणिकर्णिका फिल्म में अभिनय और निर्देशन दोनों किया है वहीं वह फिल्म पंगा में एक कलाकार भूमिका में हैं। इससे पहले कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी हैं।

मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट

सिक्किम

मनोज वाजपेयी: *सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, फिल्म भोंसले के लिए*

धनुष: *सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, फिल्म असुरन के लिए*

विजय सेतुपति
सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेता, तमिल फिल्म सुपर डीलक्स के लिए

पल्लवी जोशी: *सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेत्री द ताशकंद फाइल्स के लिए*

बी. प्राक: *सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक, फिल्म केसरी, गीतः तेरी मिट्टी में...*

सवानी रविन्द्रा: *सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका मराठी फिल्म बारदोह में रन्न पेताला गीत के लिए*

सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म : *सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म 'छिछोरे'*

पुरस्कारों की पूरी सूची देखने के लिए लिंक पर जाएं

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/mar/doc202132211.pdf

थलाइवा को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

दक्षिण भारत और फिल्मी दुनिया में थलाइवा के नाम से मशहूर रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि 5 सदस्यीय ज्यूरी ने सर्वसम्मति से उनके नाम का चयन किया। यह अवार्ड भारत की पहली फिल्म हरिश्चन्द्र बनाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर हर साल केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, "कई पीढ़ियों में लोकप्रिय। विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले। एक स्थायी व्यक्तित्व...आपके लिए रजनीकांत हो सकता है। उन्हें बधाई!!!!"

"कचरे से कंचन तो सब ने सुना है, अब कचरे को और मूल्यवान बनाने का भी काम किया जा रहा है"

यह महज संयोग है कि जब देश आजादी के 75 साल का जश्न 'अमृत महोत्सव' मना रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के लोगों से दिल से मासिक संवाद के कार्यक्रम- 'मन की बात' के 75 एपिसोड पूरे हुए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने जनता का आभार जताया और इस कड़ी में कोरोना से जंग, नारी शक्ति की प्रेरणा सहित कई ऐसी प्रेरक कहानियों को भी उन्होंने साझा किया जो आत्मनिर्भर अभियान के दौर में लोगों का दृष्टिकोण बदल रही है ...

- जनता कर्फ्यू: पिछले साल मार्च में जनता ने कर्फ्यू के बारे में सुना था जो अनुशासन का एक अभूतपूर्व उदाहरण था। आज यह गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। हमारे कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान, थालियां बजाना, तालियां बजाना, दीपक जलाना। आपको अंदाजा नहीं है कि यह इस सब ने कोरोना योद्धाओं के दिलों को कितना छू लिया था।
- अमृत महोत्सव: अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरु हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे सेनानियों ने देश की खातिर असंख्य कष्ट झेले हैं। उनके त्याग और बलिदान की अमर गाथाएँ हमें कर्तव्य पथ पर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं।
- नारी शक्ति: भारत की नारी शक्ति के लिए खेल एक पसंदीदा विकल्प है। हाल ही में, क्रिकेटर मिताली राज 10 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनीं। आज शिक्षा से लेकर उद्यमिता, सशस्त्र बल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक, देश की बेटियां हर जगह एक अलग मुकाम बना रही हैं।
- स्वीट रिवॉल्यूशन: बी-फार्मिंग स्वीट रिवॉल्यूशन के लिए अग्रणी भूमिका में है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद कर रहा है। बनासकांठा में किसानों ने एक नया अध्याय लिखा और आज यह हनी (शहद) उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। पूरी दुनिया आयुर्वेद और प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों की ओर देख रही है और शहद की मांग तेजी से बढ़ रही है जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है।
- लाइट हाउस पर्यटन: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 71 लाइट हाउस की पहचान की गई है। इनमें संग्रहालय, कैफेटेरिया, चिल्ड्रन पार्क आदि को उनकी क्षमताओं के अनुसार बनाया जाएगा। गुरू प्रसाद जी ने 2019 में चेन्नई और महाबलिपुरम लाइटहाउस के हेरिटेज म्यूजियम की यात्रा के बारे में बात की, जो मरीन नेविगेशन के इतिहास को सामने लाता है।
- प्रेरक कहानियां: कुछ ही दिन पहले विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है। बनारस के रहने वाले इंद्रपाल सिंह बत्रा जी ने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनाए हैं जिसमें गौरैया आसानी से रह सकें।

  कार्बी भाषा: कार्बी एनॉलांग गांव के रहने वाले सिकारी टिस्सौ पिछले 20 साल से कार्बी भाषा को सहेजने का काम कर रहे हैं जिससे कार्बी भाषा पुन: मुख्यधारा में वापस आ गई है।

  कचरे से कंचन: विजयवाड़ा के प्रो. श्रीनिवास पदकांडला जी ने ऑटोमोबाइल स्क्रैप से मूर्तियां (स्कल्पचर्स) बनाए हैं। ये विशाल मूर्तियां सार्वजनिक पार्कों में लगाई गई हैं और लोग उत्साह से देखने आते हैं। केरल में कोच्चि के सेंट टेरेसा कॉलेज के छात्र रियुजेबल खिलौने बेहद रचनात्मक तरीके से बना रहे हैं। यह छात्र पुराने कपड़ों, फेंके गए लकड़ी के टुकड़ें, बैग और बॉक्स से खिलौने बना रहे हैं। तमिलनाडु के कोयंबटूर में बस कंडक्टर का काम करने वाले मरिमुथु योगनाथन यात्रियों को टिकट के साथ एक पौधा मुफ्त में देते हैं और अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा इसमें खर्च करते हैं।

'मन की बात' पूरी सुनने के लिए QR कोड Scan करें

PMO India @PMOIndia · 6d
मौतुवा शॉम्प्रोदाय के हमारे भाई-बहन श्री श्री हॉरिचान्द ठाकुर जी की जन्मजयंति के पुण्य अवसर पर हर साल 'बारोनी स्नान उत्सव' मनाते हैं।

भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होने के लिए, ओराकान्दी आते हैं: PM @narendramodi

Rajnath Singh
मेरे संसदीय क्षेत्र लखनऊ में ट्रैफिक जाम से मुक्ति हेतु पिछले कुछ वर्षों में कई फ़्लाइओवरों का निर्माण कार्य किया गया है। इसी क्रम में, आज एक और फ़्लाइओवर का लोकार्पण किया जाएगा और एक नए फ़्लाइओवर की आधारशिला भी रखी जाएगी। इन फ़्लाइओवरों के बन जाने से जनता के लिए आवागमन सुगम होगा।

Amit Shah
स्वतंत्रता के इतिहास में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की वीरता व योगदान को शब्दों में वर्णित करना सम्भव नहीं है। देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने की उनकी तड़प और बलिदान को याद कर आज भी हर भारतवासी की आँखें नम हो जाती हैं।

ऐसे वीर बलिदानियों के चरणों में कोटिशः नमन।

Nitin Gadkari
2020-21 में भारत ने विश्व में सबसे तेज राजमार्गों का निर्माण किया है। भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इस मुक़ाम तक पहुँचाने में अन्यान्य अधिकारियों और कर्मियों ने अपना सर्वज्ञ दिया है। उन सभी का अभिनंदन। #PragatiKaHighway

Thawarchand Gehlot
देश में सामाजिक समरसता स्थापित करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के कल्याण और न्याय की आवाज उठाने वाले महानायक भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है।

Gajendra Singh Shekhawat
जल जीवन मिशन ने स्थापित किया नया आयाम।
15 अगस्त, 2019 को मिशन की शुरुआत से अब तक 4.01 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पहुंचाया जा चुका है नल से शुद्ध जल।
कुल 7.24 करोड़ (37.78%) ग्रामीण परिवारों को मिल रहा नल से शुद्ध जल।
#HarGharJal
#JalJeevanMission

ढाका से मोदी का संदेश, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...

कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण समय की जरूरत : मोदी

सवाल था टीका कब आएगा, अब सबसे बड़ा अभियान भारत में: मोदी
पीएम ने कहा- 'दवाई भी, कड़ाई भी' यह मंत्र याद रखिए

भारत ने फिजी को भेजी कोरोना वैक्सीन की एक लाख खुराकें
अहम रक्षा सौदों पर मुहर लगाएंगे भारत-अमेरिका

कृषि क्षेत्र में फौरन सुधार की जरूरत : मोदी

आर.एन.आई
DELHIN/2020/78812
16-30 अप्रैल 2021

न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर -
DL (S)-1/3550/2020-22 डब्ल्यूपीपी संख्या U (S)-98/2020-22, posting at BPC,
Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly
(प्रकाशन तिथि - 5 अप्रैल 2021, कुल पृष्ठ-44)

बीज से बाजार की विकास यात्रा

प्रधानमंत्री ने दिया नैनीताल के किसान खीमानंद के पत्र का जवाब

प्रिय खीमानंद जी

कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु सरकार के सतत प्रयासों पर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए आपका आभार। किसान हितैषी फसल बीमा योजना का लाभ आज करोड़ों किसान ले रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में व्यापक कवरेज और पारदर्शी दावा निस्तारण प्रक्रिया के माध्यम से यह योजना किसान कल्याण को समर्पित हमारे प्रयासों और पक्के इरादों की एक मिसाल बन कर उभरी है। आज बीज से लेकर बाजार तक किसानों की हर छोटी-बड़ी दिक्कतों को दूर करने और अन्नदाता की समृद्धि व कृषि की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण के साथ आज देश एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर तेजी से अग्रसर है।

संपादक:
जयदीप भटनागर, प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश, प्रधान महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली-
110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट
लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल
एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20